आज का विचार
खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइये, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है..!!

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | शुक्रवार, 18 अप्रैल, 2025 वर्ष 23, अंक 97, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

वक्फ से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत

सिंघवी ने केंद्र सरकार के सुधारों को बताया अधिकारों पर हमला

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि वैचारिक हमला है। केंद्र सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है।

वक्फ को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरमैन एवं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहां आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

सिंघवी ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का अभ्यास, निर्वहन और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। वह धर्म से जुड़ी संस्थाओं का संचालन व प्रबंधन कर सकता है और उनके चुनावों में नामित हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पांच खंडपीठों के पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक वर्ग की संस्थाओं की स्वायत्तता को इस हद तक कम करना कि वह समाप्त हो जाए, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 11 में चुनावित श्रेणी को हटाकर शत-प्रतिशत नामांकन का प्रावधान स्वायत्तता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधान 9 और 14 पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रावधान 9 कहता है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 12 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं। प्रावधान 14 कहता है कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से सात गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम में एक अजीब प्रावधान है, जिसके तहत यदि बोर्ड के शत-प्रतिशत सदस्य भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, तो भी उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सरकार ऐसा न करे। यह प्रावधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों और

स्वायत्तता के खिलाफ है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ गैर-मुस्लिम भी हो सकता है, जो कि एक हास्यास्पद है।

सिंघवी ने कहा कि नए कानून के हिसाब से वक्फ बाय यूजर का कोई कानूनी अस्तित्व ही नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक जो घोषित या पंजीकृत वक्फ संपत्ति हैं, उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। सिंघवी ने आगे कहा कि अधिनियम में एक अजीबोगरीब प्रावधान है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति के बारे में आरोप लगाकर विस्तार से एक चिट्ठी लिख कर कलेक्टर को भेज देता है तो कलेक्टर उसे विवादित करार दे सकता है। इसमें कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। जब तक कलेक्टर उस विवाद का निर्णय न करे, तब तक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसमें कलेक्टर द्वारा निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम इन प्रावधानों के बारे में अपनी बात कोर्ट के सामने मजबूती से रखने वाले हैं। इस मामले को सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक की नजर से देखना सही नहीं होगा। ये संविधान की आत्मा का सवाल है। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। यह विधेयक संविधान की बराबरी की भावना पर हमला करता है।

इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ कानून में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कई बिंदुओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जेपीसी और संसद में विपक्ष के सांसदों द्वारा दिए गए सुझाव नकार दिए गए थे। उनके समेत कुछ याचिकाकर्ता वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को संविधान की जीत बताया और उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई में और राहत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बनाने और बचाने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और हमेशा उठाएगी।

सुरक्षा बलों के त्याग और तपस्या के कारण ही हम सुरक्षित : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन और संस्थान की वार्षिक थीम का शुभारंभ

एजेंसी (हि.स.)
सिरोही

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सशस्त्र बलों के सुरक्षाकर्मियों के त्याग-तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। 46 डिग्री टेंपरेचर से लेकर प्लस 46 डिग्री टेंपरेचर में रेगिस्तान के अंदर हमारी सीमाओं की वह सुरक्षा अपने जीवन का स्वर्ण काल देकर करते हैं। तभी जाकर हम सुरक्षित, आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। सेना और सीआरपीएफ को छोड़कर सभी राज्यों की पुलिस भी कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती है। यह काम एक प्रकार से ढेर सारा तनाव पैदा करने वाला है। नींद की कमी, पानी की कमी, शांत मन की कमी और हिंसा से जूझने के समय उनका मन तनाव में होता है, ऐसे में ब्रह्माकुमारीज द्वारा हमारे सुरक्षा कर्मियों को बाहर लाकर उनका मन, आत्मा और शरीर को शांति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।

गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ब्रह्माकुमारीज के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। यहां उन्होंने डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का

दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ और प्रभाग की सिल्वर जुबली की लॉचिंग की। संस्थान की इस वर्ष की वार्षिक थीम-विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान का राष्ट्रीय उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर-के अपने आत्मा को शांति की और कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से करने की दिशा में ब्रह्माकुमारीज ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। योग और अध्यात्म से मन-बुद्धि, शरीर और आत्मा को एकरूप करके ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए और चिंतन से समस्याओं के निवारण के लिए नीतियों का सृजन करना, भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। हम इस परंपरा को आज भी समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भारत ने सबसे पहले विश्व को दी। जब पूरे विश्व में लोग गुफाओं में रहते थे तब पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये हमारे उपनिषद की ऋचा ने समग्र विश्व को हमारा परिवार बनाया।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी व्याधि काटकर आज विश्व में पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कुछ ही सालों में विश्व में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। परंतु विश्व में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनने के साथ ही हमारी जो परंपराएं हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाने की क्षमता पड़ी है। हर मानव के अंदर रही आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति हमारी परंपराओं में पड़ी है। हर जीवन को सद्वृत्ति को नई राह पर ले जाने की हमारी परंपराओं में शक्ति पड़ी है। इतनी ही तेजी के साथ आगे ले जाना यह भारत का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए ब्रह्माकुमारी जैसी संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं जो हमारे उद्देश्य को बहुत जल्दी से पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। जिनकी प्रतीक्षा देश दशकों से कर रहा था। अनुच्छेद 370 का स्थायी समाधान, कश्मीर घाटी में शांति और नवाचार और प्रगति की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इससे कश्मीर में अलगाववाद और आंतकवाद के मंसूबे परास्त हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध आपकी जीरो टालरेंस की नीति के चलते वे क्षेत्र जो कभी भय और हिंसा के पर्याय थे, आज शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे।

ब्रह्माकुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने कहा कि यदि अपने ही मन में शांति नहीं है तो हम कितनी ही कॉन्फ्रेंस कर लें, शांति की बात कर लें लेकिन कोई फायदा नहीं होगा।

राष्ट्रपति को निर्देश देना असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति ने उठाए सवाल

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर विचार के लिए तीन महीने का समय तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का अधिकार है लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहां राष्ट्रपति को निर्देशित किया जा सके और वह भी किस आधार पर। धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा इंटर्न के छठे बैच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा होता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा ली जाती है। वहीं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश ये सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं।

उन्होंन कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति रखता है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में यह दिन भी देखना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति ने कड़े शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर विधेयक अपने आप कानून बन जाएगा। उन्होंने कहा, हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करे या नहीं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र नहीं चाहा था। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्यपालिका का काम करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक विषयों पर पांच या उससे अधिक न्यायाधीश फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा, जिन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति को वस्तुतः एक आदेश जारी किया और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया कि यह देश का कानून होगा।

दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, वक्फ कानून के लिए धन्यवाद दिया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम के लिए उन्हें धन्यवाद किया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि यह संशोधन समुदाय की लंबे समय से मांग थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर भरोसा जताया।

केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मुलाकात का वीडियो साझा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया, जो उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर उनका भरोसा बहुत ही प्रेरक था।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से गुरुग्राम जमीन सौदा मामले में लगातार तीसरे दिन की पूछताछ

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के ग्रुरुग्राम में स्थित जमीन से जुड़े सौदा मामले में लगातार तीसरे दिन लगभग 6.30 घंटे तक पूछताछ की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा से इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 6-6 घंटे की पूछताछ की थी। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कल पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से रवाना हो गए।

ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जितने दिन भी बुलाएं, हम उपस्थित होंगे। वाड्रा ने कहा कि सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इनके जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ग्रुरुग्राम में स्थित जमीन सौदा से जुड़ा ये मामला साल 2008 का है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी

स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी। इस जमीन का म्यूटेशन कुछ घंटों में ही पूरा करवा लिया गया। इसके तुरंत बाद हरियाणा की सरकार ने वाड्रा की कंपनी को इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी बनाने का लाइसेंस दे दिया। वाड्रा की कंपनी ने कुछ महीनों बाद जून, 2008 में वह जमीन डीएलएफ यूनिवर्सल को करीब 58 करोड़ रुपये में बेच दी और कुछ ही महीनों में करीब 50 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया। इसके बाद साल 2018 में एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर इसकी जांच चल रही है।

दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले दो दिन गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

देश के ज्यादातर राज्यों में दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.6 ड्ग्रिी सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3-4 डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 16 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती स्थितियां बनी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश की उम्मीद है। राजस्थान में 19 अप्रैल से हीटवेव खत्म होने जा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की संभावना, 17 से लेकर 23 अप्रैल तक पूर्वोत्तर राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। 19 अप्रैल को राजस्थान और 18 अप्रैल को सौराष्ट्र और कच्छ में उष्ण लहर की स्थिति कम होने की संभावना है।

20 अप्रैल तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जिसकी अधिकतम तीव्रता 18 और 19 अप्रैल को होगी। 18 से 20 अप्रैल, के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

शुक्रवार को दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सतह पर तेज हवाएं चलेंगी जिनकी रफ्तार 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चल सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की बारिश एवं बूंदाबांदी के साथ गरज, धूल भरी आंधी के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। यह हवाएं बढ़कर 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रविवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सतह पर स्थायी हवाएं 15-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

नूरपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा, चिट्टे मामले में अब तक छह लोग गिरफ्तार, 3 करोड़ की संपत्ति और नगदी बरामद

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत बीते साल 27 अक्टूबर 2024 को पुलिस थाना डमटाल के अन्तर्गत नशा तस्करों से पकड़े गए 262 ग्राम चिट्टे की परतें खुलने लगी हैं।चिट्टे के इस बड़े खेल में आरोपितों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं पुलिस ने बड़ी गंभीरता के साथ इस मामले में अब तक छह नशा तस्करों को सलाखों के पीछे धकेला है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक करीब 3 करोड़ की चल व अचल संपत्तियों को नियमानुसार जब्त किया गया है।

एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि चिट्टे का यह खेल दुबई से ऑपरेट हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें पंजाब और हिमाचल के कांगड़ा जिला से सम्बंधित हैं।

जिला पुलिस नूरपुर द्वारा गुप्त रूप से इस अभियोग की आगामी जांच जारी रखी गई तथा जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर बीते 13 अप्रैल को नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी राज कुमार उर्फ सेठी पुत्र दौलत राम निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगडा को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की गई।

जांच यह भी पाया गया है कि गिरफ्तार आरोपी राज कुमार उर्फ सेठी पुत्र दौलत राम निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगडा का एक कुख्यात चिट्टा तस्कर है, जिस पर अन्य मामले भी दर्ज हैं। आगामी जांच के आधार पर बीते 15 अप्रैल को एक अन्य आरोपी लखविन्द्र कोहली पुत्र हरंबस लाल निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा को श्रटमेसा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी लखविन्द्र कोहली से की गई पूछताछ के आधार पर एक अन्य आरोपी मोहित सिंह उर्फ टोनी पुत्र गुरपाल सिंह निवासी सुंदरनगर पठानकोट के रिहायशी मकान की छापामारी अमल में लाई गई। छापामारी मोहित सिंह के घर से 4 लाख 90 हजार की नकदी व 67.93 ग्राम सोने के गहने, 95.45 ग्राम चांदी के गहने, 2 मोबाईल फोन व 2 एलआईसी बांड भी बरामद किये गए। आरोपी कोहली द्वारा चिट्टा बेचकर अर्जित की गई सम्पति जिसमें जेवरात व नकदी शामिल है को पुलिस के पकड़े जाने के डर से पठानकोट निवासी गगन सरना पुत्र स्व सुदेश सरना निवासी हाउस नम्बर 24/1/84 सेनगढ़ तहसील व जिला पठानकोट के पास रखी है। जिस पर जिला पुलिस नूरपुर द्वारा पेशेवर ढ़ग के कार्य करते हुये आरोपी गगन सरना के निवास स्थान पठानकोट में 6 मार्च को छापामारी करके भारी मात्रा में नकदी व जेवरात मिले, जिनमे 1 किलो 25 ग्राम सोना 04 ग्राम चांदी व एक करोड़ पन्द्रह लाख की नकदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

एसपी ने बताया कि इस मामले में गिरफतार आरोपी लखविन्द्र कोहली का बेटा विशाल भी थाना नूरपुर में मुख्य आरोपी है जिससे कुल 1 किलो 131.14 ग्राम हीरोईन/चिटटा, 100 नशीली गोलियां और कुल 1 करोड़ 04 लाख 45 हजार 300 रुपये की राशि बरामद की गई थी। आरोपी विशाल उच्च न्यायलय शिमला से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा है। वहीं इस मामले में वीरवार एक और आरोपित मोहित सिंह टोनी, पुत्र गुरपाल सिंह, निवासी सुंदरनगर पठानकोट को भी गिरफतार कर लिया गया है।

एसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपितों को गिरफतार किया जा चुका है। वहीं इस मामले में 262 ग्राम चिट्टा, 1 किलो 92.93 ग्राम सोने के गहने, 99.45 ग्राम चांदी के गहने व कुल 1 करोड़ 19 लाख,90,000 हजार की नकदी, 2 मोबाईल फोन व 2 एलआईसी बांड की बरामदगी की जा चुकी है। इसके अलावा इन आरोपितों और इनके रिश्तेदारों के नाम विभिन्न बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। जिनमें 52 लाख 52 हजार 424 रुपये की राशि जमा है।

इसके अलावा विभिन्न स्थानों की भूमि के दस्तावेज, 6 वाहनों के कागजात व 3 वाहन चाबियां, 6 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, 10 लाख की दो जीवन बीमा पॉलिसियां तथा दो कारें भी बरामद की हैं।

तुफान का कहर, संस्कृति सदन मंडी का पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

बुधवार की रात को मंडी जिले में तुफान के कहर ने खूब तबाही मचाई। हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए, टहनियां टूट कर मकानों पर जा गिरी, हजारों होर्डिंग तुफान में उड़ गए, टीन की कई छत्तें हवा में लहराते हुए दूर जा पहुंची। रात को ही बिजली गुल हो गई जो गुरूवार को देरी से बहाल हो पाई। मंडी के कांगनीधार में 35 करोड़ से निर्मित हुआ संस्कृति सदन चारों तरफ से चीड़ के पेड़ गिरने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लाखों का नुकसान इस भवन का हुआ है। अभी भी इस अति महत्वपूर्ण भवन के चारों तरफ खतरनाक पेड़ हैं जो आने वाले दिनों में भी कहर बरपा सकते हैं।

इस सदन में भाषा एवं संस्कृति विभाग व जल शक्ति विभाग के कार्यालय भी चल रहे हैं, आडिटोरियम में भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, विश्राम गृह भी इसके अंदर बना हुआ है। गनीमत यह रही कि तुफान रात के वक्त आया, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। इस बहुमंजिला भवन के क्षतिग्रस्त हो जाने से अब असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है। लाखों खर्च करके ही इसकी मरम्मत हो पाएगी।

विभागों ने उपायुक्त को इसकी रिपोर्ट भेज दी है तथा खतरनाक पेड़ों को हटाने की भी मांग की गई है। यह भी पता चला है कि काफी अरसे से वन विभाग से गुहार लगाई जा रही थी कि इन खतरनाक पेड़ों को हटाया जाए मगर ऐसा हो नहीं सका और इस तुफान के कहर से टूटे पेड़ों ने तीन साल पहले बने इस आलीशान भवन को बुरी तरह से तोड़ डाला। पूरे जिले में तुफान के कहर से भारी नुकसान की खबर है। बिजली के खंबे उखड़ जाने से जगह जगह बिजली गुल है। रात भर बिजली गुल रहने व दिन को भी देर से आने के चलते लोग सुबह नहाने धोने का काम भी नहीं कर पाए। मोबाइल भी चार्ज नहीं हुए। पूरा जनजीवन ही इस तूफान ने अस्त व्यस्त कर दिया। रात को व्यावसायिक परिसरों के बाहर रखे होर्डिंग बैनर या बोर्ड सुबह तूफान के कहर के चलते गायब पाए गए। सड़कों पर पेड़ों की टहनियां, तारें , फलैक्स, टीनें आदि ही नजर आती रही। साथ में बारिश भी जमकर हुई, जिससे गंदम की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा। तुफान व बारिश से फलदार पौधों को भी नुकसान हुआ। कई जगह तो फलों के साथ साथ पते भी जमीं पर जा पहुंचे। किसी तरह की जानी नुकसान की खबर नहीं है।

निजी स्कूलों पर डम्मी एडमिशन पर कसेगा शिकंजा, रद्द होगी संबद्धता

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में चल रहे डम्मी एडमिशन के खेल को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बोर्ड द्वारा अब इन स्कूलों का औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। औचक निरीक्षण में यदि किसी निजी संस्थान में डम्मी एडमिशन पाई जाती है तो संबद्धता रेगुलेशन के निर्धारित नियमों के तहत संस्थान को प्रदान की गई संबद्धता को सक्षम अधिकारी द्वारा तुरंत वापिस ले लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों बारे बोर्ड कार्यालय में दूरभाष व अन्य माध्यम से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर लिया है।

शिकायतों में कहा जा रहा है कि कुछ संस्थानों द्वारा अपने विद्यालय में डम्मी एडमिशन करवाई जाती है अर्थात छात्र/छात्रा द्वारा दाखिला किसी शिक्षण संस्थान में लिया होता है, जबकि वह उसी समय अन्य स्थान पर कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा होता है। ऐसे मामलों में सीबीएसई बोर्ड द्वारा उनसे संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की इस सन्दर्भ में जांच की जा रही है और जांच में यदि यह पाया गया कि संस्थानों द्वारा डम्मी एडमिशन करवाई गई है तो ऐसे संस्थानों की संबद्धता रद्द करने पर भी विचार किया जा रहा है।

उधर, बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त निजी शिक्षण संस्थानों से आग्रह किया है कि वह अपने संस्थान में किसी भी विद्यार्थी को डम्मी एडमिशन न दें तथा संबद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियमानुसार ही संस्थान का संचालन करें। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया है कि वह भी निजी शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण करेगा। यदि औचक निरीक्षण के दौरान किसी संस्थान में डम्मी एडमिशन पाई जाती है तो संबद्धता रेगुलेशन में इस बारे पहले से ही निर्धारित नियम 16.13.7 के अन्तर्गत संस्थान को प्रदान की गई संबद्धता को सक्षम अधिकारी द्वारा तुरन्त वापिस ले लिया जाएगा, जिसके लिए संस्थान प्रबंधन स्वंय उत्तरदायी होगा।

डेरा की गली राजौरी में गुज्जर और बक्करवाल समुदायों को स्लीपिंग बैग किए गए वितरित

एजेंसी (हि.स.)
राजौरी

सामाजिक कल्याण और सामुदायिक आउटरीच के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने डेरा की गली राजौरी में गुज्जर और बक्करवाल समुदायों के सदस्यों को स्लीपिंग बैग वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य इन खानाबदोश समूहों के लिए बहुत जरूरी गर्मी प्रदान करना और उनके रहने की स्थिति में सुधार करना है खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है।

यह वितरण समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए भारतीय सेना के निरंतर समर्पण का प्रतिबिंब है। आउटरीच स्थानीय आबादी के साथ संबंधों को मजबूत करने और विश्वास, समावेशिता और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य को भी पूरा करता है। गुज्जर और बक्करवाल समुदायों का समर्थन करके भारतीय सेना न केवल एक रक्षक के रूप में बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करती है। यह प्रयास सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है, स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और सर्दियों के दौरान सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देता है। इसके अलावा यह कट्टरपंथी विचारधाराओं और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रति संवेदनशीलता को रोकते हुए एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद करता है। भारतीय सेना अपने दोहरे मिशन में दृढ़ बनी हुई है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश भर में सेवा करने वाले समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाती है।

संक्षिप्त-समाचार

सिरमौर के प्रकाश ठाकुर का एशिया कप के लिए भारतीय पेसापालो टीम में चयन

नाहन। सिरमौर जिले के प्रकाश ठाकुर ने हिमाचल का नाम एक बार फिर रोशन किया है। शिलाई क्षेत्र के टिम्बी गांव से संबंध रखने वाले प्रकाश का चयन भूटान में आगामी पेसापालो एशिया कप के लिए भारतीय सीनियर टीम में हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 27 मई से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। प्रकाश ठाकुर वर्ष 2016 से पेसापालो खेल से जुड़े हुए हैं और इससे पहले भी भारत की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और समर्पण से न केवल प्रदेश बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पेसापालो फेडरेशन ऑफ इंडिया से एशिया कप के लिए चयन पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करेगी।

मोबाइल पर इनकमिंग कॉल वाले तीन पाकिस्तानी फोन नंबर मिलने के बाद पुंछ निवासी गिरफ्तार

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के एक निवासी को गुरुवार को सांबा जिले से तब गिरफ्तार किया गया, जब उसके मोबाइल फोन पर इनकमिंग कॉल वाले तीन पाकिस्तानी फोन नंबर मिले। अधिकारियों ने कहा कि पुंछ जिले के निवासी फारूक अहमद को सांबा में तब हिरासत में लिया गया, जब उसके फोन पर इनकमिंग कॉल वाले तीन पाकिस्तानी फोन नंबर मिले। उसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास देखा गया, जिससे संदेह पैदा हुआ और उसे हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस अब उसकी संदिग्ध गतिविधियों से उसके संभावित संबंधों की जांच कर रही है। सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान में किसी भी आईएसडी कॉल की अनुमति नहीं है। जम्मू संभाग के कठुआ, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में आतंकवादियों का पता लगाने और संयुक्त बलों का उन्हें मुठभेड़ में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर ह्यखोजो और नष्टह्न करो अभियान चल रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं ने जम्मू में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

जम्मू। भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करना विपक्षी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील है जिसके नेता गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को प्रतिशोध की कार्रवाई करार देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है जिसमें उन पर कथित तौर पर 988 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप लगाया गया है। विधायक युद्धवीर सेठी और अरविंद गुप्ता समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और नेता कच्ची छावनी चौक पर एकत्र हुए और कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उनके पुतले जलाए। विधायक सेठी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के ताबूत में आखिरी कील है। कांग्रेस द्वारा किया जा रहा विरोध और प्रतिशोध की राजनीति के आरोप निराधार हैं क्योंकि वे नेशनल हेराल्ड अखबार को आवंटित सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग में शामिल हैं। वे सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर यह कदम उठाया है और कांग्रेस नेताओं को भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए जेल की सजा होगी। पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने भी कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी संलिप्तता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बजाय वे बेशर्मी से देश भर में कांग्रेस कार्यकताओं का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए कर रहे हैं। मां-बेटे की जोड़ी अपने कार्यकताओं को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करके लोगों को धोखा देने और अपने घोटालों को छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपने नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के खिलाफ बुधवार को देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को प्रदर्शन करने का अधिकार हो सकता है लेकिन उसे नेशनल हेराल्ड अखबार को आवंटित सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है।

साइबर पुलिस कश्मीर ने श्रीनगर और गांरबल जिलों में कई जगह पर की छापेमारी

श्रीनगर। वित्तीय साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए साइबर पुलिस कश्मीर ने स्थानीय पुलिस थानों के साथ मिलकर गुरुवार को श्रीनगर और गांरबल जिलों में कई जगह छापेमारी की। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर और गांदरबल में कम से कम तीन स्थानों पर आज सुबह छापेमारी की गई जिसमें उन व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो कथित तौर पर उनके नाम पर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे और जिन्हें आमतःौर पर खच्चर खाते कहा जाता है। सूत्रों ने पुष्टि की कि साइबर पुलिस कश्मीर द्वारा विश्वसनीय इनपुट और तकनीकी निगरानी के बाद छापेमारी शुरू की गई थी। साइबर पुलिस कश्मीर उन व्यक्तियों के नेटवर्क की जांच कर रही है जिन्होंने अपनी क्रेडेंशियल्स की अनुमति दी है।

ऊना में कांग्रेस का रोष, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)
ऊना

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दायर की गई चार्जशीट के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यकताओं ने ऊना मुख्यालय पर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन की अगुवाई उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। कांग्रेस कार्यकताओं ने एमसी पार्क ऊना में धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।इसके उपरांत एमसी पार्क से लेकर रोटरी चौक तक रोष रैली निकाली।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लागातर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी परिवार ने हमेशा देश हित में आवाज बुलंद की है, जिनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।केंद्र सरकार ईडी व सीबीआई को राजनीतिक हथियार बना रहे है। जांच एजेंसियों का दुरुप्रयोग कर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई कर जनता का मुददों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के खिलाफ की गई कार्रवाई निंदनीय है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निडर है। केंद्र सरकार के षडयंत्रों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुप्रयोग बंद नहीं किया और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का काम जारी रहा तो कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी दिनों में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से आज देश में महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। देश की जनता का महंगाई से बुरा हाल हो रहा है। बेरोजगार सडकों पर भटक रहा है। केंद्र सरकार ऐसे मुददों से जनता का ध्यान भटकाकर विपक्षों दलों को टारगेट करने में लगी हुई है।

रोष प्रदर्शन में गगरेट के विधायक राकेश कालिया, चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा, ऊना सदर से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकताओं ने भाग लिया।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने गुरु रविदास को सामाजिक न्याय का मशाल वाहक बताया

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने गुरु रविदास को सामाजिक न्याय, समानता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बताया। कविंदर गुप्ता ने श्रद्धेय संत की शिक्षाओं की सराहना की जो देश भर में पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने जातिगत भेदभाव और असमानता से मुक्त समाज की कल्पना की थी। उनकी शिक्षाएँ सार्वभौमिक भाईचारे, करुणा और श्रम की गरिमा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि उनका संदेश अब भी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।

गुरु रविदास के समावेशी दर्शन पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि संत की कविता और आध्यात्मिक दृष्टि एक ऐसे समाज की वकालत करती है जहां हर व्यक्ति- जाति या पंथ की परवाह किए बिना- सम्मान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।

भारत की डीपटेक कंपनी सिंप्लिफोर्ज ने हिमालय में सबसे अधिक ऊंचाई पर ऑन-साइट 3ऊप्रिंटेड ढांचा बनाकर एक नया ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित किया

एजेंसी (हि.स.)
लेह

डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए सिंप्लिफोर्ज क्रिएशंस और आईआईटी हैदराबाद ने समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊँचाई पर लेह में भारत की पहली ऑन-साइट 3ऊप्रिंटेड सुरक्षात्मक मिलिट्री स्ट्रक्चर का निर्माण सफलतापूर्वक किया है। भारतीय सेना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट प्रबल के तहत इसका निर्माण किया गया है। यह उपलब्धि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर इन-सीटू 3डी कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग की रिकॉर्ड बनाने वाली घटना बन गई है। इसे अत्यधिक ऊँचाई और कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों में पूरा किया गया है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर के.वी.एल. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में सिंप्लिफोर्ज क्रिएशंस और आईआईटी-हैदराबाद की टीमों ने विशेष रूप से ऐसी 3डी प्रिंटिंग तकनीक विकसित की जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में काम कर सके। इसे कुल चौदह घंटे की प्रिंटिंग अवधि में पूरा किया गया है। सिंप्लिफोर्ज क्रिएशंस के सीईओ ध्रुव गांधी ने इस अवसर पर कहा लेह के ऊंचाई और कम-ऑक्सीजन वाले वातावरण में इस परियोजना को क्रियान्वित करना हमारी टीम और मशीनों दोनों के लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती थी। रोबोटिक प्रिंटर सिस्टम को 24 घंटों के भीतर सेट-अप और चालू किया गया जो इसके फुतीर्लेपन और स्पीड को दशार्ता है।

अंबेडकर के विजन के प्रति भाजपा प्रतिबद्ध : विबोध

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चल रहे डॉ. भीम राव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत भाजपा जम्मू-कश्मीर के महासचिव और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने पुंछ में भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। यह अभियान भारतीय संविधान के मुख्य निमार्ता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है।

विबोध गुप्ता ने कांग्रेस पर डॉ. अंबेडकर की विरासत पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंबेडकर को दरकिनार कर दिया गया और यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उचित मान्यता भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान ही डॉ. अंबेडकर का चित्र संसद में रखा गया था और भाजपा समर्थित सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। उन्होंने अंबेडकर के जीवन को सम्मान देने के लिए पंच तीर्थ-पांच समर्पित स्थल-स्थापित करने और अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के अनुरूप दलितों के उत्थान के उद्देश्य से योजनाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा की। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विबोध ने नेशनल हेराल्ड मामले में गहरी जड़ें जमाए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पार्टी पर गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट साजिशों को अंजाम देने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध भूमि अधिग्रहण और भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों को मोदी की ईमानदार सरकार के तहत कानून का सामना करना पड़ेगा। पुंछ के भाजपा जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए कहा कि मोदी सरकार हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाकर और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करके अंबेडकर के मूल्यों को बनाए रखने के लिए वास्तव में काम कर रही है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेंजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित- 160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का निर्णय लिया

संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब राज्य के पीएम श्री, मॉडल संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों में 857 योग सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा योग व्यायामशालाओं के जीर्णोद्धार करने के कार्य के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राज्य सरकार का राजकीय योग शिक्षा और स्वास्थ्य महाविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है, इसके लिए भूमि नारायणगढ़ या आसपास के क्षेत्र में भूमि चिन्हित की जाएगी। हरियाणा आयोग के चेयरमैन व अन्य सदस्यों ने इस संबंध में आज बैठक से पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की।

ये निर्णय यहाँ आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा योग आयोग की समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भूमि की पहचान करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत विभाग को राज्य में निर्मित योग व्यायामशालाओं का जीर्णोद्धार करने और एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आयुष चिकित्सकों की योग दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें हरिद्वार स्थित पतंजलि योग केंद्र तथा पट्टी कल्याणा व पानीपत स्थित योग प्रशिक्षण केंद्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजेगी।

बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पूर्व प्रदेश के सभी जिलों में 4 दिवसीय योग शिविर (कार्यशालाएं) शुरू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 में 1,000 नए योग व्यायामशालाओं के निर्माण की योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रारंभिक सुविधाएं स्कूलों में संचालित की जाएंगी। सभी जिला स्तरों पर शहरी स्थानीय निकायों की भूमि पर आयुष योग केंद्रों के निर्माण के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि यह कार्य अंबाला और सोनीपत में पहले ही किया जा चुका है और एचएसवीपी के अधीन पार्कों का उपयोग ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए किया जा सकता है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों से चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में राजकीय योग शिक्षा और स्वास्थ्य महाविद्यालय के मॉडल का अध्ययन करने को कहा।

बैठक में हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि 21 जून को पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 25 दिन पूर्व आयोग द्वारा 27 मई 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2000 आयुष योग सहायक, आयुष विभाग के अधिकारी तथा योग संस्थाओं के प्रतिनिधि सूर्य नमस्कार अभियान में भाग लेंगे। सूर्य नमस्कार अभियान-2025 के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले विभागों/संस्थाओं/खिलाड़ियों को 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संबंधित जिला अथवा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा प्रणाली में योग को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की क्षमता निर्माण बढ़ाया जाए। उन्होंने योग के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम बनाने का आग्रह किया, जिसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। बैठक में हरियाणा खेल विभाग की खेल नीति-2015 में योग जैसे गैर ओलम्पिक खेलों को शामिल करने तथा योगासन खेल के खिलाड़ियों को अन्य प्रतिष्ठित खेलों की तरह ग्रेडेशन, नकद पुरस्कार, छात्रवृत्ति आदि लाभ प्रदान करने पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर आयुष महानिदेशक श्री संजीव वर्मा, हरियाणा योग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. रोशन लाल, रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक

संवाददाता

चंडीगढ़

- घर-घर जाकर बच्चों के टीकाकरण व पौष्टिक आहार की दी जा रही जानकारी- श्रुति चौधरी

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण 22 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, परंपरा के मिश्रण से बच्चों, महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि यह पोषण पखवाड़ा बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों पर केंद्रित है क्योंकि यह बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। इस दौरान प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में छह वर्ष तक के बच्चों के लिए वजन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोषण पखवाड़े के तहत गांव-गांव तक संतुलित आहार और एनीमिया के बारे में जनता को जागरूक किया जाए। बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु जागरूक किया जाए।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इसको लेकर एक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसके अनुसार सभी सुपरवाइजर अपने अपने सर्कल में गतिविधियां करवा रहे हैं। पोषण अभियान के तहत मातृत्व पोषण और स्तनपान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दो वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण घर-घर जाकर किया जा रहा है। जन समुदाय में पोषण ट्रैकर के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, माताओं के लिए पौष्टिक थाली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है।

पोषण पखवाड़ा के तहत ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत मातृ और शिशु पोषण लाभार्थियों के लिए स्वयं डिजिटल पंजीकरण करने की जानकारी दी जाएगी। अति कुपोषित बच्चों के लिए मातृ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उनके खान-पान का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। 8 अप्रैल से शुरू हुए पोषण पखवाड़ा के दौरान विभिन्न विभागों के समन्वय से अनेकों गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण अभियान, पोषण वॉक, साइकिल रैली, योग सत्र, ग्राम सभा बैठकें, पोषण बैठक, ऑनलाइन/वेबिनार, प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं। पिछले साल पखवाड़े के दौरान 3,63,480 गतिविधियां की गई थी जिसमें 5.17 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।

हरियाणा में रबी विपणन सीजन में फसल की खरीद का कार्य तेजी से बढ़ रहा है आगे

संवाददाता

चंडीगढ़

- एक अप्रैल से अब तक 31.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद
- 15 मार्च से अब तक 4.93 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है

हरियाणा में रबी विपणन सीजन के दौरान तेजी से फसल खरीद का कार्य चल रहा है। बीती एक अप्रैल से अब तक प्रदेश भर में कुल 31.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 8.59 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 2 लाख से अधिक किसानों से गेहूं की खरीद की गई है तथा 14 सौ करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जा चुकी है। पिछले वर्ष 16 अप्रैल तक 18.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी।

राज्य में रबी विपणन सीजन 2025 - 26 के दौरान 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की गई है। राज्य में दो खरीद संस्थाओं हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा सरसों की खरीद का कार्य किया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि इस साल 16 अप्रैल तक राज्य में खरीद संस्थाओं द्वारा 4.93 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है। इसमें 3.40 लाख मीट्रिक टन सरसों का उठान किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक एक लाख 71 हजार किसानों से सरसों की खरीद की गई है तथा 1843 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल का एक - एक दाना खरीदने को प्रतिबद्ध है।

हरियाणा के मुख्य सचिव से मिले 13 देशों के 27 प्रतिनिधि

संवाददाता

चंडीगढ़

विधायी प्रारूपण (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) से संबंधित 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे 13 देशों के 27 प्रतिनिधियों ने आज यहां हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी से मुलाकात की।

कोटे डी आइवर, इक्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, श्रीलंका, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, मालदीव, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (ढफ्क्क्रुए) के सहयोग से आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने समावेशी कानून बनाने की प्रक्रियाओं के महत्व पर बल देते हुए कहा, ₹किसी भी कानून की रूपरेखा सभी हितधारकों की आवाज सुनकर ही प्रभावी ढंग से तैयार की जा सकती है।₹ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उसमें समाज की आकांक्षाओं, भावनाओं और जरूरतें प्रतिबिंबित होनी चाहिए। श्री रस्तोगी ने कहा कि भारतीय संविधान सावधानीपूर्वक तैयार किया गया दस्तावेज है और यह कानून बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा और स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इसमें सुनिर्धारित प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून मजबूत होने के साथ-साथ अनुकूलनीय भी हों। उन्होंने भारत में हरियाणा की विशिष्ट स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय और कर संग्रह वाला एक छोटा लेकिन प्रगतिशील राज्य है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत रूप से सभी विदेशी प्रतिनिधियों को श्रीमद्भगवद्गीता की एक-एक प्रति भी भेंट की। उन्होंने कहा कि महाभारत एक ऐसी कथा है, जो किसी की भी कल्पना से परे है, जिसमें कर्म का महान सिद्धांत निहित है। जीवन में ऐसे हालात आते हैं, जब व्यक्ति को सांत्वना और सहारे की जरूरत होती है। ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता हमारे लिए शक्ति-स्तंभ का काम करती है। मुख्य सचिव ने कहा कि जब आप अपने देशों को लौटेंगे, तो आप अपने साथ न केवल पेशेवर अंतर्दृष्टि बल्कि हमारी परंपराओं की गर्मजोशी और सहयोग की भावना भी ले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच ज्ञान को साझा करना और विधायी मसौदा तैयार करने के कौशल को बढ़ाना है। इसमें उन्नत प्रारूपण तकनीक, तुलनात्मक विधायी रूपरेखा और विधायी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से संबंधित सत्र शामिल हैं।

इक्वाडोर के वित्तीय नीति और विनियमन निकाय के निदेशक श्री एलेजांद्रो निकोलस वीसन नेमलसेफ ने सभी प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए मुख्य सचिव का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यहां मिले प्रशिक्षण ने उन्हें न केवल अधिक कुशल पेशेवर बनाया है, बल्कि बेहतर इंसान भी बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत की मूल ताकत उसके लोगों में निहित है। भारत के लोग बेहद प्यार करने वाले और गर्मजोशी से भरे हैं और भारत आना उनके लिए एक शानदार अनुभव रहा है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग के पूर्व सचिव और पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. के.एन. चतुर्वेदी ने इस अवसर पर विदेशी प्रतिनिधियों के लिए एक महीने के पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त-समाचार

डीएचबीवीएन की लापरवाही पर आयोग सख्त, उपभोक्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिजली विभाग की खामियों के चलते शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सिरसा निवासी श्री रघबीर सिंह ने आयोग को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन लेने के बाद निर्धारित सब्सिडी के लिए आवेदन किया था, परंतु निगम द्वारा उन्हें यह लाभ प्रदान नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने सब्सिडी के लिए सभी पात्रताएं पूरी की थीं। उनका कनेक्शन 20 किलोवाट से कम लोड का है और इकाई ह्यसीह्ल श्रेणी खंड में आती है। आयोग के प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता श्री रघबीर सिंह, जो कि एक औद्योगिक इकाई के संचालक हैं, विद्युत सब्सिडी के पूर्णतः पात्र हैं। उनकी इकाई ह्यसीह्ल श्रेणी खंड में आती है तथा कनेक्शन का लोड 20 किलोवाट से कम है, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर आता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 को जारी पत्र का हवाला देकर शिकायतकर्ता की पात्रता को नकारा गया और पूर्व प्रभाव से नई शर्तें थोप दी गईं, जो आयोग के अनुसार न केवल प्रशासनिक रूप से गलत, बल्कि कानूनी रूप से भी अमान्य हैं। शिकायतकर्ता को अनेक बार एस.डी.ओ. कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े, जिससे उन्हें अत्यधिक मानसिक परेशानी हुई। आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता पर किया गया चार्जबैक निरस्त करे और दिनांक 21 दिसंबर 2018 या विद्युत कनेक्शन की तिथि (जो भी बाद में हो) से 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बकाया सब्सिडी जारी करे। यह समस्त कार्यवाही 28 अप्रैल 2025 तक पूर्ण की जाए। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(एच) के अंतर्गत शिकायतकर्ता को पाँच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए, जो निगम अपने स्वयं के कोष से देगा और संबंधित दोषी अधिकारियों से वसूली करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 25 अप्रैल से

चंडीगढ़ । महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 25 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों (यूजी/पीजी एनईपी 2020 प्रोग्राम्स समेत) की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 25 अप्रैल से 6 मई 2025 तक आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेटशीट समेत अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

ईडी को हथियार बनाकर भाजपा सरकार राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है: कुमारी सैलजा

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है, देश के सामने सच्चाई लाना चाहता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब भी कोई सच्चाई देश के सामने लाना चाहते है तो ये सरकार ईडी को हथियार बनाकर उनकी आवाज को दबाना चाहती है पर भाजपा भूल जाती है कि वे कांग्रेस न कभी किसी के आगे झुकी है और न ही झुकेगी, देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। राहुल गांधी का गरीबों के घर जाना, बेरोजगारों के साथ खड़े होना, जनहित में आवाज उठाना भाजपा को अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि आज पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या उसे सच का आइना दिखाता है उस पर ईडी को हथियार बनाकर हमला किया जाता है, एजेएल क्या है सबको पता है पर उसके नाम पर केंद्र सरकार राहुल गांधी, सोनियां गांधी को घेरना चाहते है पर कांग्रेस और उसके नेता न कभी झुके नहीं है और न ही झुकेंगे। सोनिया गांधी ने इस देश की खातिर बहुत कुछ न्यौछावर किया है, त्याग किया है।

नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी ने मिलकर करने होंगे प्रयास- महिपाल ढांडा

संवाददाता

चंडीगढ़

- साइक्लोथॉन यात्रा ड्रग फ्री हरियाणा में निभा रही है महत्त्वपूर्ण भूमिका

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के मार्गदर्शन में ड्रग फ्री हरियाणा को लेकर निकाली जा रही साइक्लोथॉन-2.0 का पानीपत जिला सचिवालय परिसर में पहुंचने पर प्रशासन की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने साइक्लोथॉन यात्रा के यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व उन्होंने 84 गांवों की पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशंसा पत्र व ट्रॉफी प्रदान करके ड्रग फ्री कार्य में अहम भूमिका निभाने पर सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर ओलंपियन पहलवान सीमा बिसला और कॉमनवेल्थ गेम की ब्रांज मेडल विजेता पूजा गहलावत को ट्राफी देकर सम्मानित किया और परिसर में मौजूद सभी आयोजकों, खिलाड़ियों, व कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई।

शिक्षा श्री महीपाल ढांडा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। साइक्लोथॉन यात्रा जहां-जहां से गुजर रही है वहां-वहां नशे को दूर करने का संदेश दे रही है। जिला प्रशासन भी नशे पर लगाम कसने को लेकर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इस कार्य में लगातार सफलता हासिल हो रही है। कानून के माध्यम से भी नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है।

उन्होंने कहा कि नशे का जाल को तोड़ने के लिए सरकार लड़ाई लड़ रही है। नशे जैसी बीमारी को मिटाने के लिए समाज की भूमिका अहम रहती है। शिक्षा मंत्री ने नशे के खिलाफ जारी इस मुहिम में आह्वान किया कि युवा इस मुहिम का हिस्सा बनें व इस समस्या को बाहर निकालने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि इस नशे जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है। इस मुहिम से लाखों जिंदगियां बचेंगी। लोग प्रेरणा लेकर नशे को तिलांजली देंगे। यह यात्रा खास तौर पर युवाओं में उनके जीवन में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह और पानीपत एसडीएम ब्रहमप्रकाश मौजूद रहे।

श्रम विभाग द्वारा सभी जिलों में चलाया जा रहा 10 दिवसीय पंजीकरण अभियान संपन्न

संवाददाता

चंडीगढ़

- ई - श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उमड़ी श्रमिकों की भीड़
- ब्लिंकिट, स्विग्गी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स से शामिल हुए श्रमिक

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में पिछले 10 दिन से गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों के लिए चलाया जा रहा विशेष पंजीकरण अभियान आज संपन्न हो गया।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के दौरान श्रम विभाग को गिग वर्कर्स की बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और बड़ी संख्या में उनका पंजीकरण किया गया है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य इस पहल के अंतर्गत एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इस अभियान के दौरान राज्य के सभी जिलों में जागरूकता और पंजीकरण शिविर लगाए गए जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया। इस दौरान कई स्थानों पर श्रमिकों की सक्रीय भागीदारी और भारी भीड़ देखने को मिली।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रिंट मीडिया, पेम्पलेट वितरण, जन घोषणाएं, घर - घर जाकर जनसम्पर्क, सोशल मीडिया अभियान तथा स्थानीय निकायों और श्रम कल्याण अधिकारीयों के सहयोग से जागरूकता फैलाई गई। इसके अलावा ब्लिंकिट, स्विग्गी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अर्बन कंपनी जैसी पलटफोर्म आधारित कंपनियों से संपर्क किया गया और इस पंजीकरण अभियान के बारे में जानकारी दी गई ताकि वे इसमें भाग ले सकें।

गौरतलब है कि श्रम विभाग के ई - श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 54 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। इस ऑनलाइन पंजीकरण का आरम्भ 2021 में किया गया था और बीती 7 अप्रैल से खासतौर से गिग वर्कर्स के लिए पहली बार पंजीकरण अभियान चलाया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफार्म आधारित कर्मचारियों को भारत सरकार के ई - श्रम पोर्टल से जोड़ना था। यह पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो असंगठित श्रमिकों को औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

संवाददाता

चंडीगढ़

- अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करने के मामले में सौंपा ज्ञापन

हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी से आज यहां हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के प्रावधान को लागू न कर सभी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करने के लिए ज्ञापन सौंपा।

श्री कृष्ण कुमार बेदी ने प्रतिनिधिमंडल को उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और इस मामले में भी नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी एक मामले में हरियाणा सरकार द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को जारी हिदायतों को सही माना है व सभी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति देना उचित ठहराया है। साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर को लागू करने बारे भी हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए हैं। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार व इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मामले में संवैधानिक पीठ द्वारा यह तय किया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग पर क्रीमीलेयर लागू नहीं होता।

ऊर्जा मंत्री के नए फामूर्ले को लागू करने हेतू अधिकारियों को निर्देश, नागरिकों को निर्बाध और पूर्ण वोल्टेज वाली बिजली 24 घंटे होगी उपलब्ध

विज ने ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन व नई बुलंदियों को छूने के लिए बिजली कंपनियों को दिए मंत्र

संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ-साथ नई बुलंदियों को छूने के लिए राज्य की बिजली कंपनियों को ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने नए मंत्र देते हुए संबंधित अधिकारियों को विभिन्न दिशानिर्देश दिए हैं जिसके तहत हरियाणा के नागरिकों को निर्बाध और पूर्ण वोल्टेज वाली बिजली 24 घंटे उपलब्ध होगी। श्री विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18240 गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को अगले एक महीने में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा तथा भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली का बिल जमा करने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। श्री विज ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के 538.13 करोड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के 1500 करोड रूपए की डिफाल्टर बकाया राशि है जिसे वसूलने के लिए अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए है। इस लक्ष्य के तहत यूएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 100 करोड, मई 2025 में 200 करोड तथा जून 2025 में 238 करोड रूपए की डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा। इसी प्रकार, डीएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 300 करोड, मई 2025 में 600 करोड तथा जून 2025 में 600 करोड रुपए डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा। श्री विज ने यह निर्देश गत दिवस चण्डीगढ में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। श्री अनिल विज ने इस बैठक में बिजली कंपनियों को घाटे उभारने, बिजली चोरी को रोकने व मामलों के समाधान, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने, लंबित राशि को वसूलने, डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनैक्शन, उपभोक्ताओं के आधार को बिजली कनेक्शन से लिंक करने, डिफाल्टर राशि को वसूलने के लिए लक्ष्य, गलत बिजली बिल पर कार्यवाही/सुधार, बिजली अदालतें, तारों/फीडर की जांच करने बारे, कॉल सेंटर तथा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के बारे में निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी कनेक्शन की डिफॉल्टर राशि के संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क किया जाए और मुख्यालय स्तर पर फाइल प्रस्तुत की जाए ताकि त्वरित बिजली बिलों की

बकाया राशि की वसूली की जा सके। इसी प्रकार, उन्होंने पुराने डिफॉल्टर (पुराने पीडीसीओ कनेक्शन) के संदर्भ में निर्देश दिए कि पहले चरण में उन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं जिनकी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत डिफॉल्टर राशि यूएचबीवीएन में 80,000 रूपए से अधिक और डीएचबीवीएन में एक लाख रूपए से अधिक है। बैठक में यह भी बताया गया कि पुराने पीडीसीओ (परमानेंट डिसकनैक्ट आर्डर) मामलों में आर-एपीडीआरपी प्रणाली में डुप्लिकेट बिलों के कारण वास्तविक लंबित राशि कहीं कम है। इस संबंध में श्री अनिल विज ने निर्देश दिए कि डुप्लिकेट/इंनफिलेटेड बिलों की पहचान कर तत्काल सुधार किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस किया जाए जिन्होंने अन्य सब-डिवीजन के अंतर्गत नया कनेक्शन ले लिया है। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए कि औद्योगिक, एनडीएस एवं शहरी डीएस श्रेणी में कोई भी डिफॉल्टर उपभोक्ता नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता का आधार बिजली कनैक्शन से लिंक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पीडीसीओ उपभोक्ताओं की फील्ड ऑफिस द्वारा नियमित जांच की जाए ताकि बिजली चोरी कर अनधिकृत रूप से उपयोग न किया जा रहा हों। श्री विज ने प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सर्कल स्तर पर ह्यह्यबिजली अदालतह्लह्ल आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि बिजली बिल संबंधित शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्रत्येक अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक बिजली बिल की शिकायत के निवारण को सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि बड़ी संख्या में चोरी के मामले ह्यह्यजांचाधीनह्लह्ल हैं। इस संबंध में श्री विज ने निर्देश दिए कि भारी राजस्व वाले चोरी मामलों में चार्जशीट दायर कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ को चोरी पकड़ने की उचित प्रक्रिया जैसे एलएल-1 तैयार करना, सबूत इकट्ठा करना, एफआईआर दर्ज करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाए और इस संबंध में एक प्रशिक्षण वीडियो बनाकर फील्ड स्टाफ में दी जाए ताकि फील्ड स्टाफ अपनी डयूटी का निर्वहन सही प्रकार से कर सकें।

संपादकीय

भारत का समग्र विकास स्थायी जनजातीय उत्थान के साथ ही संभव है

जी हां यह बात सौलह आने सच है कि भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनजातीय समुदायों से जुड़ा है, जो देश की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक संरचना में गहराई से रचे-बसे हैं। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जनजातीय विकास के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम तो बनाए गए, किंतु वास्तविक धरातल पर इन समुदायों की स्थिति आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। यदि भारत को समग्र और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए जनजातीय उत्थान अनिवार्य है। 2005 में माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए भारत सरकार की ह्यरणनीतिक बस्तीह्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ के हजारों गोंड जनजातियों को उनके पैतृक स्थानों से विस्थापित कर दिया गया। लगभग दो दशक बीतने के बाद भी ये परिवार न तो अपने मूल स्थान लौट सके हैं और न ही उन्हें नए राज्यों में जनजातीय दर्जा प्राप्त हो सका है। यह केवल एक उदाहरण है, जो दशार्ता है कि देश भर में जनजातीय समुदायों को किस प्रकार की प्रशासनिक अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता और सांस्कृतिक विच्छेदन का सामना करना पड़ रहा है।आइये विस्तार से समझते हैं भारत की विकास यात्रा में जनजातियों की भूमिका के बारे में। भारत की सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय समुदायों का अमूल्य योगदान रहा है। गोंड, भील, संथाल, वारली जैसी जनजातियाँ लोककथाओं, पारंपरिक नृत्य, संगीत और चित्रकला में न केवल दक्ष हैं, बल्कि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित भी कर रही हैं। वारली चित्रकला आधुनिकता की लहर में भी अपनी पहचान बनाए रखी है।गोंड कला को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा रहा है। जनजातीय समुदायों का जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित होता है। उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा में सहायक रही हैं।डोंगरिया कोंध जनजाति ने ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों को बॉक्साइट खनन से बचाया।बस्तर की जनजातियों ने खनन और वनों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाई है।झारखंड की मुंडा जनजाति, ओडिशा की संथाल जनजाति जैसे समूह मिश्रित फसल प्रणाली, पारंपरिक बीज और प्राकृतिक खाद का उपयोग कर संधारणीय कृषि को बढ़ावा देते हैं।इनकी तकनीकें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर पाने में भी मददगार हैं।जनजातीय समुदायों की हस्तशिल्प, वस्त्र, हर्बल दवाएँ और अन्य पारंपरिक उत्पाद वैश्विक बाजार में पहचान बना रहे हैं।इससे आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है।उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित जनजातियों ने सुरक्षा बलों को स्थानीय जानकारी और समर्थन देकर माओवादी प्रभाव को कम करने में सहायता की है।छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजातीय युवाओं की सुरक्षा बलों में भर्ती एक सकारात्मक संकेत है। इस में कोई दो राय नहीं हैं कि जनजातीय समुदायों के समक्ष कई चुनौतियाँ होती हैं । जनजातियों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान उनकी पैतृक भूमि से जुड़ी होती है, किंतु औद्योगीकरण और विकास परियोजनाओं ने उन्हें बार-बार उजाड़ा है।ओडिशा और छत्तीसगढ़ में खनन परियोजनाओं ने लाखों जनजातियों को विस्थापित किया।कोया जनजाति अपनी ही भूमि में मजदूर बन गई है।जनजातीय युवाओं को अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।इ एम आर एस जैसे स्कूलों की पहल सराहनीय है, किंतु उनमें ड्रॉपआउट दर उच्च बनी हुई है।जनजातीय महिलाओं में एनीमिया का स्तर 64% तक पहुँच गया है।पाँच वर्ष से कम उम्र के 40% से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।जनजातियों को वनों से प्राप्त संसाधनों के उचित मूल्य नहीं मिलते, जिससे वे गरीबी के चक्र में फँसे रहते हैं।झारखंड, ओडिशा और मध्यप्रदेश में खनन उद्योगों में जनजातीय श्रमिकों का शोषण आम है।शहरीकरण और मुख्यधारा की संस्कृति के प्रभाव में पारंपरिक कलाएँ, भाषाएँ और त्योहार धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं।वन अधिकार अधिनियम के बावजूद अधिकांश राज्यों में इसके क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है।गुजरात सरकार ने 40% से अधिक दावों को खारिज कर दिया। साक्ष्य की सूची के बिना निर्णय लेना न्यायसंगत नहीं।सरकार इन चुनौतियों के मद्देनजर कई उपाय कर रही है और नीतियां भी बना रही है। इस अधिनियम ने जनजातियों को उनके पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया, लेकिन व्यवहार में कई समस्याएँ सामने आई हैं।पंचायतों को जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन राज्य सरकारों की अनिच्छा इसके कार्यान्वयन में बाधा बनी हुई है।जनजातीय छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित विद्यालय।जनजातीय उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इससे जनजातीय इतिहास को राष्ट्रीय पहचान मिली है।विस्थापित जनजातियों को उनके नए राज्यों में जनजातीय दर्जा प्रदान करना अनिवार्य है, ताकि उन्हें सभी सरकारी लाभ मिल सकें।जनजातीय बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा और स्थानीय संदर्भों में पाठ्यक्रम आवश्यक है।पोषण मिशन में जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और जनजातीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नेटवर्क सुदृढ़ किया जाए।पी ई एस ए को जमीनी स्तर पर लागू कर स्वराज की अवधारणा को साकार किया जाए।वनों से प्राप्त संसाधनों का स्वामित्व अधिकार जनजातीय समुदायों को देकर उनके जीवन-यापन को सुरक्षित किया जाए।जनजातीय युवाओं को डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। अंत में कह सकते हैं कि भारत के समग्र विकास की यात्रा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक हमारे वनवासी भाइयों को समान अवसर, अधिकार और पहचान नहीं मिलती। जनजातीय समुदाय केवल संरक्षण के पात्र नहीं, बल्कि विकास के सक्रिय साझेदार हैं। उनकी सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय जागरूकता और सामाजिक संरचना भारत को एक स्थायी और समावेशी राष्ट्र बनाने में मदद करती है। यह आवश्यक है कि नीति निमार्ताओं, समाज और मीडिया का ध्यान इस दिशा में केंद्रित हो, ताकि जनजातीय उत्थान केवल सरकारी रिपोर्टों तक सीमित न रहे, बल्कि वह एक सामाजिक क्रांति के रूप में साकार हो।

सामुदायिक नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की रेडियो तरंगें

डॉ. बृजेन्द्र सिंह पंवार

निकिता जोशी

हैशटैग, जीआईएफ और रील्स की इस डिजिटल दुनिया में, संचार विभिन्न माध्यमों तक फैल गया है। आज भारत का एक बड़ा हिस्सा, इंटरनेट और इसके द्वारा संभव त्वरित संचार के बिना विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी यह सोचना गलत होगा कि प्रभावी संचार एकतरफा माध्यम तक ही सीमित है। लक्षित दर्शकों और उनके सांस्कृतिक संदर्भों का अध्ययन करने से विभिन्न संचार माध्यमों का पता लगाने में मदद मिलती है, जिन्हें व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप शुरू किया गया और अपनाया गया है।

सामुदायिक रेडियो एक ऐसा रचनात्मक माध्यम है जो आज देश के विभिन्न भागों में फल-फूल रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।रेडियो सेट सबसे किफायती है और इसका स्वामित्व और संचालन प्रायः आर्थिक रूप से सबसे निचले स्तर वाले व्यक्ति के पास भी होता है। इस संचार माध्यम के मूल में समुदाय के नेतृत्व वाले स्वामित्व और जमीनी स्तर पर अभिव्यक्ति के मूल्य निहित हैं। यह एक ऐसा मंच है जो समुदायों को अपनी भाषा में खुद को अभिव्यक्त करने और उन मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है जो उनके अस्तित्व के मूल में हैं। इस प्रकार के माध्यम न केवल साझेदारियां बनाते हैं, संचार और प्रबंधन कौशल विकसित करते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक भी बनते हैं।इसलिए सरकारें इन स्थानीय संचार प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो मजबूत समुदायों के निर्माण में भी मदद करते हैं।

सामुदायिक रेडियो सही मायने में ह्यविश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स), 2025ह्व में 'रेडियो वेव्स' बनाने के लिए तैयार है, जिसका आयोजन 1 से 4 मई, 2025 तक मुंबई में किया जाएगा। वेव्स का आयोजन भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक बाजारों से जोड़ने, विकास, सहयोग और नवाचारों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ किया जा रहा है। वेव्स का मुख्य उद्देश्य उद्योग विकास को गति देना, नवाचार को बढ़ावा देना, युवा प्रतिभा को सशक्त बनाना और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना है। सामुदायिक रेडियो का पंजीकृत व निर्वाचित संगठन, भारतीय सामुदायिक रेडियो संघ (सीआरएआई), भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से, भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के विकास को प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेव्स में कई पहलों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है।

सामुदायिक रेडियो सामग्री चुनौती, ह्य32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंजह्व में से एक है। इस पहल के तहत 32 चुनौतियों में से प्रत्येक को कौशल का परीक्षण करने और युवाओं को एनीमेशन, गेमिंग, ईस्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म निर्माण आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक प्रतिष्ठित मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है ! सामुदायिक रेडियो सामग्री चुनौती का उद्देश्य, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित विविध कौशल और विशिष्ट आवाजों को उजागर करना तथा उन्हें नए प्रारूपों, शैलियों और कहानी कहने की तकनीकों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इससे सामुदायिक रेडियो के लिए ज्ञान साझा करने, एक-दूसरे से सीखने और संपर्क बनाने के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

यह चैलेंज उन कार्यक्रमों को मान्यता देगा और पुरस्कृत करेगा जो अपने समुदायों में वास्तविक बदलाव लाते हैं।इस चुनौती के लिए प्रविष्टियां पांच श्रेणियों से मांगी गई हैं- सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षा और साक्षरता, महिला और बाल विकास/सामाजिक न्याय, कृषि और ग्रामीण विकास तथा सांस्कृतिक संरक्षण। प्रतिष्ठित मीडिया हस्तियों और सीआरएआई के प्रतिनिधियों सहित विशेषज्ञों का एक पैनल इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगा, प्रतिभागियों की सूची बनाएगा और अंततः विजेताओं का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करेगा।

इसके अलावा, सीआरएआई, वेव्स आयोजन के दौरान क्रिएटोस्फीयर में एक सामुदायिक संपर्क क्षेत्र स्थापित करेगा। इस सामुदायिक संपर्क क्षेत्र का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के मूलभूत सिद्धांतों और विभिन्न समुदायों के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करना है। सामुदायिक संपर्क क्षेत्र के प्रमुख तत्व हैं-सामुदायिक रेडियो स्टेशन संग्रह प्रदर्शन फ्लिप बुक, सीआरएस इंडिया मानचित्र या रेडियो गार्डन, एक लाइव रेडियो सेट अप और एक न्यूजलेटर।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन संग्रह प्रदर्शन करने वाला फ्लिप बुक एक आकर्षक, इंटरैक्टिव फ्लिप बुक है जिसमें पूरे भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पहलों का एक व्यापक संग्रह होगा। उपस्थित लोग इस डिजिटल संग्रह को ब्राउज करके सामुदायिक रेडियो के उभरते परिदृश्य को समझ सकते हैं तथा स्थानीय और क्षेत्रीय आख्यानों को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और सफलता की कहानियों के बारे में जान सकते हैं।

देश भर में सक्रिय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति को दशार्ने के लिए भारत का एक बड़ा, इंटरैक्टिव मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, रेडियो गार्डन अवधारणा का उपयोग किया जाएगा, जहां आगंतुक भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रसारित विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वर्चुअल रूप से देख और सुन सकेंगे। इससे आगंतुकों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत आवाजों और मुद्दों की विविधता को समझने में मदद मिलेगी।

वेव्स सामुदायिक रेडियो सामग्री चुनौती से उत्पन्न नवीनतम घटनाक्रम, गतिविधियों और पहलों को दशार्ने वाला एक न्यूजलेटर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के सामने आने वाली रचनात्मक चुनौतियों और उनकी प्रतिक्रियाओं पर विचार शामिल होंगे। यह न्यूजलेटर आगंतुकों को रेडियो प्रसारण के रुझानों और समुदाय-संचालित नवीन कार्यक्रमों के बारे में नई जानकारी देती रहेगी।

सामुदायिक रेडियो में उनके असाधारण योगदान के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन पुरस्कार विजेताओं का सम्मान करने के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित किया जाएगा। इस जगह पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, निमार्ताओं और स्वयंसेवकों की प्रोफाइल प्रदर्शित की जाएगी जिन्होंने समाज पर अपने प्रभाव के लिए पुरस्कार जीते हैं।दृश्य प्रदर्शन और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के माध्यम से उनकी कहानियों को प्रस्तुत किया जाएगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो के प्रभाव पर जोर दिया जाएगा।

एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करने के लिए, जोन के भीतर एक लाइव रेडियो सेट अप स्थापित किया जाएगा, जहां आगंतुक रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता, सामुदायिक प्रसारकों के साथ बातचीत कर सकेंगे और लाइव चचाओं में भाग ले सकेंगे।इस व्यवस्था से आगंतुकों को उसी समय के प्रसारण में भाग लेने, प्रश्न पूछने, अनुभव साझा करने और सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा।

'मन की बात' श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक अनुभाग में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से प्रसारित एपिसोड दिखाए जाएंगे।यह संकलन आगंतुकों को उन प्रमुख प्रकरणों को सुनने का अवसर प्रदान करेगा, जो विविध समुदायों को प्रभावित करते हैं, तथा महत्वपूर्ण मुद्दों, राष्ट्रीय उपलब्धियों और पहलों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे प्रसारणों ने आम जनता को कैसे जोड़ा है तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है इस पर ध्यान दिया जाएगा। देश भर के 530 से अधिक सामुदायिक रेडियो भी 1 से 4 मई 2025 के बीच वेव्स में विचार-विमर्श में भाग ले रहे हैं।

सामुदायिक रेडियो के साथ जुड़ने से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि महानगरों और टियर 1 शहरों से परे अन्य क्षेत्रों के समुदायों में प्रतिभा और उत्साह की कोई कमी नहीं है। वेव्स का उद्देश्य, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में ऐसे सभी प्रयासों के कौशल और क्षमता को सामने लाना और उन्हें जुड़ने तथा सहयोग करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। आशा है कि इस पहल का अंतिम लाभ उन समुदायों को मिलेगा जिनका प्रतिनिधित्व ये रेडियो स्टेशन करते हैं !

डॉ. बृजेन्द्र सिंह पंवार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में एम.एस. पंवार संचार एवं प्रबंधन संस्थान, सोलन के निदेशक तथा 16 वर्ष पुराने 'हमारा एमएसपीआईसीएम सामुदायिक रेडियो' सोलन के स्टेशन निदेशक हैं।
निकिता जोशी (आईआईएस 2019) वर्तमान में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो, मुंबई में सहायक निदेशक के पद पर तैनात हैं।

भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी का महत्व

बालासुब्रमण्यम अय्यर

भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी युनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी के लिए विधेयक का संसद में पारित होना भारतीय सहकारी आंदोलन की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसका 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान संपन्न होना इसके महत्व को और बढ़ाता है। जैसा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, यह युनिवर्सिटी 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने में एक शक्तिशाली माध्यम बनने के लिए तैयार है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन का घर है, जिसमें 800,000 से ज्यादा सहकारी समितियाँ और 287 मिलियन सदस्य शामिल हैं। रोटी, कपड़ा से लेकर मकान तक की जरूरतों के लिए लोगों के दैनिक जीवन में गहराई से समाहित सहकारी समितियाँ सिर्फ. आर्थिक संस्थाएँ नहीं हैं; वे समुदाय-संचालित विकास, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने इस क्षेत्र के लिए एक नई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का संकेत दिया, जिसका उद्देश्य इसकी पहुँच का विस्तार करना, इसकी दक्षता में सुधार करना और इसे समावेशी विकास की आधारशिला के रूप में एकीकृत करना है।

सहकारिता मंत्रालय ने सराहनीय कदम उठाए हैं: 67,390 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (ढअउर) को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए रु 2,516 करोड़ आवंटित करना, 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में ढअउर को सक्षम करने के लिए 32 राज्यों में मॉडल उपनियमों को लागू करना, 2 लाख नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (टढअउर) बनाने का लक्ष्य रखना, 1,100 किसान उत्पादक संगठनों को समर्थन देना और 44,000 ढअउर को सामान्य सेवा केंद्रों (उरउ) में बदलना। कर प्रोत्साहन, आसान ऋण और विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधा सहकारी समितियों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं।बीज, निर्यात और जैविक उत्पादों के लिए तीन नए राष्ट्रीय महासंघों की स्थापना इस बात का संकेत है कि सहकारी समितियों को भारत के विकास के प्रमुख एजेंट के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

परन्तु, अपने विस्तार और पहुंच के बावजूद, सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की अवरचना आंशिक, अविकसित और असमान रूप से वितरित है। प्रबंधकीय और प्रशासनिक से लेकर तकनीकी और परिचालन तक योग्य पेशेवरों की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। मौजूदा कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण में निवेश करने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है । इन कर्मचारियों में से कई के पास नियमित प्रशिक्षण या शिक्षा के अवसरों तक पहुंच नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, गुणवत्ता आश्वासन और संस्थागत सामंजस्य के बिना, यह क्षेत्र अपनी क्षमता का पूरी तरह से लाभ नहीं ले सकता है या अपने विकास को बनाए नहीं रख सकता है। सहकारी आंदोलन में नई और युवा पीढ़ियों को आकर्षित करने की भी सख्त जरूरत है - ऐसे व्यक्ति जो न केवल पेशेवर हों बल्कि सहकारी मूल्यों से प्रेरित हों और क्षेत्र में नवाचार करने के लिए आतुर हों। यहां, त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है: शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक केंद्र के रूप में सेवा करके जो नई पीढ़ी के सहकारी नेताओं को बढ़ावा देते हुए सभी स्तरों पर उनकी क्षमता का निर्माण कर सकेगा ।

अमूल मॉडल के वास्तुकार, दूरदर्शी श्री त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर, और भारत की डेयरी सहकारी क्रांति के उद्गम स्थल आनंद में स्थित यह युनिवर्सिटी एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है, साथ ही यह एक रणनीतिक हस्तक्षेप भी है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (क्म्र्टअ) का चयन - एक ऐसा संस्थान जिसने दशकों से सहकारी प्रबंधन शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है - इस युनिवर्सिटी की नींव के रूप में व्यावहारिक और प्रेरणादायक दोनों है। आनंद में क्म्र्टअ को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में नामित किए जाने के साथ, यह युनिवर्सिटी सहकारी उद्यमों की चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए सुसज्जित पेशेवरों को तैयार करने की एक मजबूत विरासत का निर्माण करेगा।

युनिवर्सिटी का विजन सिर्फ. औपचारिक प्रबंधन डिग्री तक सीमित न होकर काफी विस्तृत है । यह प्राथमिक और माध्यमिक सहकारी समितियों के बोर्ड सदस्यों, सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों, और नैतिक, सस्टेनेबल और समावेशी व्यवसाय मॉडल में रुचि रखने वाले युवाओं की नई पीढ़ी तक अपनी पहुँच बढ़ाएगा। इसके लिए, युनिवर्सिटी लचीले शिक्षण मॉड्यूल, प्रमाणन कार्यक्रम, डिग्री कार्यक्रम, डिजिटल पहुँच प्रदान करेगा और क्षेत्र-आधारित ऐसे शोध का जरिया बनेगा, जिनसे स्व-सहायता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पारस्परिक जिम्मेदारी के सहकारी मूल्यों का लाभ सभी को मिल सकेगा।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय ज्ञान मंच के रूप में भी काम कर सकता है, हितधारकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बना सकता है, साक्ष्य-आधारित नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और ग्रामीण वास्तविकताओं के अनुरूप नवाचारों का समर्थन कर सकता है। डेयरी, ऋण, आवास, मत्स्य पालन, कपड़ा आदि जैसे भारत के विविध सहकारी परिदृश्य में, विश्वविद्यालय एक ऐसे केन्द्र के रूप में विकसित होगा जहां, शिक्षा, नीति निमार्ता और सहकारिता से जुड़े विशेषज्ञ उन्नयन के नये पथ ईजाद कर सकेंगे ।

वैश्विक स्तर पर, सहकारी शिक्षा सहकारी आंदोलनों की सफलता का आधार रही है। 1844 में रोशडेल पायनियर्स के समय से ही, आचरण के मूल नियमों में मुनाफे का एक हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित करना शामिल था। पाँचवाँ सहकारी सिद्धांत - शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना - आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य, नेता और समुदाय सहकारी मॉडल को समझें और उसका पालन करें। यह गहरी जड़ें जमाए बैठी शैक्षिक परंपरा ही है जो सहकारी शासन को बनाए रखती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और जवाबदेही को मजबूत करती है।

इस संदर्भ में, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी केवल एक शैक्षणिक संस्थान से कहीं अधिक होगा - यह सहकारी विकास के लिए एक राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान केंद्र बन सकता है, एक ऐसा स्थान, जहाँ प्रयोग और नीति का संगम हो और जहां नेतृत्व सीख से प्रेरित हो । नई दिल्ली में आयोजित क्वअ वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत से सहकारी समितियों को एकजुट करने, साझा मंच बनाने, आम चुनौतियों से निपटने और सामूहिक रूप से आगे का रास्ता तय करने में वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का आ'ान किया। राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऐसा ही एक मंच प्रदान करता है - जो संवाद को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहकारी समितियों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने में सक्षम है।

एक ऐसी दुनिया में जहाँ समावेशी, लोकतांत्रिक और सतत विकास सुनिश्चित करते आर्थिक मॉडल की मांग बढ़ रही है, भारत का सहकारी आंदोलन और अब इसका पहला सहकारी यूनिवर्सिटी न केवल प्रेरणा बल्कि दिशा भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय को सुलभ, नवोन्मेषी और प्रभावोत्पादक होना चाहिए, जो आंदोलन के हर स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा दे। नींव रखी जा चुकी है; अब समय आ गया है कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो उस दृष्टिकोण के योग्य हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है - एक ऐसा संस्थान जो आने वाली पीढ़ियों को सहकारिता की अविनाशी शक्ति के माध्यम से शिक्षित, सशक्त और ऊर्जावान बनाएगा - और यह सुनिश्चित करेगा कि सहकारी समितियाँ सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें।

आज का राशिफल

मेष: मेष राशि के छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा से जुड़ी संभावनाएं दिखेंगी। अध्यात्म और धार्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन मिलेगा। युवा वर्ग करियर के प्रति गंभीर रहेंगे और नई दिशा में प्रयास करेंगे। कार्यस्थल पर अपनी क्षमता साबित करेंगे, लेकिन आर्थिक लेन-देन में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि इससे विवाद की स्थिति बन सकती है।

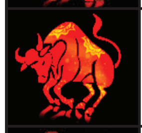
वृषभ: वृषभ राशि वालों के लिए बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विशेषकर रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोग तनाव से बचें। योग और नियमित व्यायाम लाभकारी रहेंगे। प्रेम संबंधों में धोखे की संभावना है, जिससे भावनात्मक असंतुलन आ सकता है। संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी।

मिथुन: मिथुन राशि के लिए दिन शुभ रहेगा। किसी जान-पहचान वाले के जरिए बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिससे आर्थिक स्थिरता आएगी। जॉब में प्रमोशन के संकेत हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम का संचार होगा। हालांकि, समय की कमी के कारण कोई योजना अधूरी रह सकती है। आज नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा।

कर्क: कर्क राशि के जातक प्रेमी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मानजनक पद प्राप्त हो सकता है। महिलाएं घरेलू व्यापार शुरू करने की योजना बना सकती हैं। कार्यक्षेत्र में नए बदलाव करने की सोच सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।

सिंह: सिंह राशि के विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। पारिवारिक मामलों में माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज उधार न लें और बड़े कारोबारी फैसले न करें। छात्रों को परीक्षा परिणामों में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे करियर में नई दिशा मिलेगी।

कन्या: कन्या राशि वालों को तेज गर्मी से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिलने के योग हैं। सरकारी योजनाओं से लाभ उठाने का मौका न चूकें। जीवनशैली को संयमित और सादा रखने की सलाह है। घर में बेरियत महसूस हो सकती है, परंतु किसी रचनात्मक कार्य में ध्यान लगाएं।

तुला: तुला राशि के जातक अपने मित्रों और शुभचिंतकों के प्रिय बने रहेंगे। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। आपमें आज समर्पण का भाव रहेगा और कोई रहस्य या गुप्त जानकारी उजागर हो सकती है। जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने का प्लान सफल होगा।

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेंगे। आपकी वाणी में तेज और ओज रहेगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। धन संबंधी वादे या उधारी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

धनु: धनु राशि के जातक व्यवसाय में विस्तार के लिए सक्रिय रहेंगे। आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी। रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का सही समय है। सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, यह नेटवर्किंग के नए अवसर दिला सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।

मकर: मकर राशि के जातकों को प्रबंधन संबंधी कार्यों में समस्या आ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा से बचें, यह थकावट या असुविधा ला सकती है। गलत संगति आपकी छवि पर नकारात्मक असर डाल सकती है। जीवनसाथी के साथ टकराव संभव है। प्रेम संबंधों में असमंजस की स्थिति बन सकती है।

कुंभ: कुंभ राशि वालों के कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी। आज आपके द्वारा किया गया कोई कार्य प्रशंसा प्राप्त करेगा। व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है। मित्रों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। आज अनावश्यक खर्च से बचें और बजट का पालन करें।

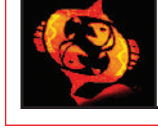
मीन: मीन राशि के जातकों को भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचना चाहिए। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को मान-सम्मान मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय रहेंगे। उच्चाधिकारियों से मुलाकात लाभप्रद सिद्ध हो सकती है।

श्री आनंदपुर साहिब हलके में 87.75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेंगे पुल: हरजोत बैंस

शिक्षा मंत्री द्वारा भाखड़ा नहर पर पांच पुलों के निर्माण की घोषणा

संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री और श्री आनंदपुर साहिब से विधायक स हरजोत सिंह बैंस ने अपने हलके में 87.75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुलों के निर्माण और ढांचागत विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और मानसून सीजन के दौरान सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है।

स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, ह्लइलाके की तस्वीर बदलने वाली ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं जहां क्षेत्र में आवागमन नेटवर्क में क्रांति लाएंगी, वहीं सैकड़ों गांवों को जोड़ने के साथ-साथ हजारों निवासियों के लिए आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि करेंगी।ह्व उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही राज्य के पवित्र स्थलों के धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि इन विकास परियोजनाओं में 34.06 करोड़ रुपए की लागत से दो पुल शामिल हैं। पहला पुल, जिसकी लंबाई 450 मीटर होगी, कलीत्तरां को बेला ध्यानी/बेला रामगढ़ से जोड़ेगा, जबकि दूसरा 300 मीटर लंबा पुल बेला ध्यानी/बेला रामगढ़ को पलासी से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि इन पुलों से कलीत्तरां, अजोली, ब्रह्मपुर, डड़ोली, भनूपली, दौणाल, नंगली और आसपास के लगभग 100-150 गांवों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, ये पुल होला मोहल्ला के दौरान एक महत्वपूर्ण बाइपास की भूमिका निभाएंगे और मानसून सीजन में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए टेंडर 30 अप्रैल 2025 को खोले जाएंगे और 29 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना भल्लड़ी से महिंदपुर-खेड़ा कलमोट तक 36.15 करोड़ रुपए की लागत से एक नया 500 मीटर लंबा पुल है। इस संरचना में चौड़े रास्ते और संपर्क सड़कें (18 फुट चौड़ी) शामिल हैं, जिससे भल्लड़ी, भलाण, पलासी, पसीवाल, भनाम, नानगरा, मोजोवाल, गोलणी, महिलवा, महिंदपुर, छोटेवाल, हाजीपुर और सुखसाल समेत 150-200 गांवों के निवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह पुल रोपड़ और होशियारपुर जिलों के बीच स्थित ऐतिहासिक श्री खुरालगढ़ साहिब (जो श्री गुरु रविदास जी के मीनार-ए-बेगमपुरा के रूप में प्रसिद्ध है) के बीच संपर्क बनाएगा और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच को भी आसान बनाएगा। इस परियोजना के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि तीसरी परियोजना में 17.56 करोड़ रुपए की लागत से स्वां नदी पर स्थित कलवां-ऐलगरां-नंगल पुल की व्यापक मरम्मत की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ब्रह्मपुर, डड़ोली, भावाल, अटारी और सरसा नगर में भाखड़ा नहर पर पांच पुल बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये ढांचागत परियोजनाएं वर्षभर और हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं ताकि विशेषकर मानसून सीजन के दौरान आवागमन बाधित न हो। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में रुचि रखने वाले योग्य ठेकेदारों और एजेंसियों को निर्धारित समयसीमा और आवश्यकताओं के अनुसार ऑनलाइन टेंडर जमा कराने का आमंत्रण दिया है।

पंजाब शिक्षा क्रांति: जालंधर जिले के सरकारी स्कूलों में 2.02 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित

संवाददाता
चंडीगढ़/जालंधर

- पंजाब सरकार की पहलों के कारण सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी: मोहिंद्र भगत

प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ह्यपंजाब शिक्षा क्रांतिह्व मुहिम के तहत आज जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 2.02 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित किए गए, जिनमें प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों में क्रमवार 63.36 लाख और 1.39 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

इसी मुहिम के तहत पंजाब के बागबानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंद्र भगत द्वारा सरकारी प्राथमिक स्कूल बस्ती शेख (लड़कियों) में 2.65 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, जिनमें एक आधुनिक क्लासरूम और फ़्लोरिंग शामिल है।

इस मौके पर स्कूल में कराए गए समारोह के दौरान संबोधन करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को हर दिशा से विकसित करने और विद्यार्थियों को मानक और समय की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की पहलों के कारण आज जहां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, वहीं सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के बराबर सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। श्री भगत ने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना, अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना, बस सेवा शुरू करना, कैंपस मैनेजर एवं सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति, डिजिटल तरीके से शिक्षा प्रदान करने जैसी कई पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने और पंजाब के बच्चों का भविष्य सुरक्षित एवं रौशन बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्रांति का आगाज किया गया है और आने वाले दिनों में भी इस मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों में विकास कार्य समर्पित किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं और यहां दी जा रही सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र करतारपुर से विधायक बलकार सिंह द्वारा सरकारी प्राथमिक स्कूल दित्तू नंगल, बीसरामपुर, नाहरपुर और पतड़ कलां एवं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतड़ कलां तथा सरकारी मिडिल स्कूल फाजिलपुर में 45.77 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य स्कूलों में भी विकास कार्य समर्पित किए गए, जिनमें क्लासरूम, प्रयोगशाला, चारदीवारी, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष और आवश्यक मरम्मत के काम शामिल हैं।

स्वर्गीय साहेब श्री काशी राम के पारिवारिक सदस्यों द्वारा जसवीर सिंह गढ़ी का सम्मान

संवाददाता
चंडीगढ़

बहुजन आंदोलन के नायक स्वर्गीय साहेब श्री काशी राम के पारिवारिक सदस्यों द्वारा आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी का सम्मान किया गया।

पारिवारिक सदस्यों में साहेब श्री काशी राम के भाई हरबंस सिंह, भतीजी बीबी भूपिंदर कौर, भतीजा बलविंदर सिंह, किरनजीत कौर के अलावा समाजसेवी मास्टर रामपाल वियाणा, जगतार सिंह टिब्बा टप्परियां, रक्षकपाल रोपड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स. भगवंत सिंह मान द्वारा एक सच्चे बहुजन नेता को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त करके पंजाब राज्य के दलितों को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि स. जसवीर सिंह गढ़ी लंबे समय से दलित लोगों को उनके अधिकारों और देश के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते रहे हैं और अब इस पद पर रहते हुये वाले दलित लोगों को न्याय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने 2024-25 के दौरान विभिन्न कार्यों पर 155 करोड़ रुपये किए खर्च: लाल चंद कटारुचक्क

संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ-सुथरा और हरियाली भरा पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यह विचार आज यहां सेक्टर-68 के वन परिसर में वन और वन्यजीव सुरक्षा मंत्री श्री लाल चंद कटारुचक्क द्वारा 2024-25 में विभाग द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और 2025-26 में शुरू होने वाले भावी कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान प्रकट किए। मंत्री को बताया गया कि 2024-25 के दौरान विभिन्न कार्यों पर लगभग 155 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

- प्रदेश सरकार वन अधीन भूमि के क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयासशील: कैबिनेट मंत्री

पौधों लगाने के कार्यों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रदेश की नर्सरियों में बनाए गए शौचालयों के बारे में मंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 100 नर्सरियों में, 2024-25 सीजन के दौरान 78 नर्सरियों में शौचालयों का निर्माण किया गया है जबकि 2025-26 सीजन के दौरान बाकी बची नर्सरियों में भी शौचालयों का निर्माण पूरा किया जाएगा। मौजूदा सीजन के दौरान लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके संबंध में मंत्री द्वारा अधिकारियों को इन पौधों की सही देखभाल और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पेड़ों की गणना के बारे में मंत्री को बताया गया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सड़कों और नहरों के किनारे खड़े पेड़ों के संबंध में हर 5 वर्षों के बाद की जाती है। मंत्री ने ह्यनानक बगीचियांह्व और ह्यपवित्र वनोंह्व में जामुन, बोहड़ और आंवला जैसे अन्य फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए और वी.सी. के दौरान मौजूद डी.एफ.ओज. को हाईवे के साथ पौधे लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण पार्कों को विकसित करने और वन्यजीव अभ्यारण जैसे कथलौर वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहिया बीड़ क्षेत्र और बमियाल जैसे अन्य सुंदर स्थानों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस मौके पर अन्य प्रमुख लोगों में प्रमुख मुख्य वनपाल धर्मिंदर शर्मा, ए.पी.सी.सी.एफ.-कम-सी.ई.ओ., पनकैंपा सौरव गुप्ता और ए.पी.सी.सी.एफ. बसंत राज कुमार भी मौजूद थे।

संक्षिप्त-समाचार

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

चंडीगढ़ / श्री मुक्तसर साहिब / मलोट।मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य में चलाई जा रही ह्यशिक्षा क्रांतिह्व के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री पंजाब डॉ. बलजीत कौर द्वारा मलोट हलके के विभिन्न स्कूलों में आज विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। स्कूलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार द्वारा ह्लपंजाब शिक्षा क्रांतिह्व के तहत ये सभी कार्य करवाए जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की और उन्हें प्रेरित किया कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक नया मुकाम हासिल करें। उन्होंने कहा कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सहायता से वे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, पायलट आदि बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा उत्तम शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यदि बच्चे अपने अध्यापकों और माता-पिता की सलाह को ध्यानपूर्वक मानें तो वे अच्छे इंसान बन सकते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सरकारी प्राइमरी स्कूल सोथा में 3 लाख रुपये, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोथा में 20 लाख रुपये, सरकारी प्राइमरी स्कूल रुपाणा में 7.51 लाख रुपये, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं) रुपाणा में 21 लाख रुपये, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालक) रुपाणा में 22 लाख रुपये और सरकारी प्राइमरी स्कूल (बालिकाएं) रुपाणा में 20.75 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जशन बराड़, चेयरमैन मार्केट कमेटी मलोट, अश्विनी बांसल डी.एस.एम., श्री रमेश अनीर्वाला (कोऑर्डिनेटर, शिक्षा क्रांति मुक्तसर साहिब), हरविंदर सिंह खलारा (स्मार्ट स्कूल कोऑर्डिनेटर), जसविंदर पाल शर्मा (जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर), गगनदीप सिंह (ब्लॉक प्रधान), स्कूली बच्चे और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

फर्जी डोप टेस्ट रिपोर्टें जारी करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में विजीलेंस ब्यूरो द्वारा घोटाले का पदार्फाश

चंडीगढ़। पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने जिला कपूरथला के सरकारी अस्पताल भुलत्थ में चल रहे एक घोटाले का पदार्फाश किया है, जहाँ कुछ कर्मचारी फर्जी नेगेटिव डोप टेस्ट रिपोर्टें जारी करने के बदले रिश्वत वसूल रहे थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए विजीलेंस ब्यूरो ने वार्ड अटेंडेंट मनप्रीत सिंह उर्फ सोनू तथा ठेका-आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर भोलू उर्फ इस्माईल को 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उक्त अस्पताल में तैनात डॉ. मोहितपाल और एक अस्थायी लैब तकनीशियन मान सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आज यहां जानकारी देते हुए राज्य विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से नेगेटिव डोप टेस्ट रिपोर्ट जारी करने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। आगे की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी नियमित रूप से डोप टेस्ट के नतीजों में हेराफेरी कर रिश्वत लेते थे और इन फर्जी रिपोर्टों का इस्तेमाल हथियार लाइसेंस प्राप्त करने या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए किया जाता था। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांग संबंधी ऑडियो/वीडियो सबूतों के साथ-साथ असली और फर्जी रिपोर्टें भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में दिनांक 17.04.2025 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 7-अ, तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के अंतर्गत विजीलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर रेंज में एफआईआर नंबर 19 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विजीलेंस ब्यूरो, जालंधर रेंज इस मामले से जुड़े अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच कर रहा है और भ्रष्ट आचरण का पूरी गंभीरता से पदार्फाश किया जाएगा।

पंजाब की शिक्षा क्रांति राज्य में शैक्षिक स्तर को और ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी: लालजीत सिंह भुल्लर

चंडीगढ़ / तरनतारन। पंजाब की शिक्षा क्रांति राज्य में शैक्षिक स्तर को और ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी और सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलने से विद्यार्थियों का मनोबल और भी ऊंचा होगा। यह प्रकटावा पंजाब के कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने आज हलका पट्टी के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कराए गए कार्यों का उद्घाटन करते हुए किया। स. भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शिक्षा क्रांति के माध्यम से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रही है और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को लगातार और अधिक मजबूत बना रही है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए निर्धारित किया है, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारा जा सके।

युद्ध नशों विरूद्ध 48वें दिन भी जारी: पंजाब पुलिस ने 471 स्थानों पर छापेमारी करके 97 नशा तस्कर किये काबू

संवाददाता
चंडीगढ़

- पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
- दिनभर चले ऑपरेशन के दौरान 60 एफआईआर दर्ज, 40.9 लाख रुपये ड्रग मनी और 261 ग्राम हेरोइन बरामद

प्रदेश में नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किए गए ह्लयुद्ध नशों विरूद्धह्व को लगातार 48वें दिन भी जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने आज 471 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 97 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 60 एफआईआर दर्ज की गईं। इस प्रकार केवल 48 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 6402 हो गई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 40.9 लाख रुपये ड्रग मनी, 261 ग्राम हेरोइन, 699 ग्राम अफीम और 1997 नशीली गोलियां/कैप्सूल भी बरामद किए हैं।

यह ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निदेर्शों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एकसाथ चलाया गया।

जिक्रयोग है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुपरडंट ऑफ पुलिस को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 84 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों द्वारा राज्य भर में छापेमारी की गई और दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 502 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की है।

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति - इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस द्वारा इस रणनीति के डी-एडिक्शन हिस्से के रूप में 6 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए प्रेरित किया गया है।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर की नई अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया का शुभारंभ किया

संवाददाता
चंडीगढ़/जालंधर

पंजाब सरकार में बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज जालंधर की नई अनाज मंडी में गेहूं की पहली खेप के आगमन पर औपचारिक रूप से गेहूं खरीद प्रक्रिया की शुरूआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने, समय पर तुलाई और किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस सीजन के दौरान जिले की 79 मंडियों में लगभग 5.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के आगमन की संभावना है। उन्होंने कहा कि अब तक 2101 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुँच चुका है, जिसकी खरीद कर ली गई है और 100 फीसदी किसानों को भुगतान किया जा चुका है। इस अवसर पर जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉ.हिमांशु अग्रवाल, मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुरपाल सिंह और जिला मंडी अधिकारी अरविंदर सिंह भी उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मंडियों में किसानों की गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में बंपर फसल उत्पादन को देखते हुए गेहूं की खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 29 अस्थायी मंडियों की भी व्यवस्था की गई है।

कैबिनेट मंत्री और डिप्टी कमिश्नर ने मंडियों में पीने योग्य पानी, सफाई व्यवस्था, छाया, तिरपालों और आवश्यक मात्रा में बारदाने की उपलब्धता जैसे सभी जरूरी प्रबंधों का भी जायजा लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के निदेर्शों के अनुसार संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और कुशलता से अंजाम दिया जाएगा।

इस मौके पर गांव गाखल से किसान संतोख सिंह, जो नई अनाज मंडी, जालंधर में गेहूं की पहली खेप लेकर आए थे, ने गेहूं खरीद प्रक्रिया के लिए किए गए प्रबंधों पर संतोष व्यक्त किया।

स्थानीय निकाय मंत्री ने विधान सभा शाम चौरासी के चार स्कूलों में 33 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का किया उद्घाटन

पंजाब शिक्षा क्रांति केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की लहर: डा. रवजोत सिंह

संवाददाता
चंडीगढ़ \ होशियारपुर

पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे ₹ पंजाब शिक्षा क्रांति₹ अभियान के अंतर्गत आज विधान सभा शाम चौरासी के चार सरकारी स्कूलों में स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने करीब 33 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अभियान का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि ₹पंजाब शिक्षा क्रांति₹ अब केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की लहर है जो हर गांव, हर स्कूल और हर बच्चे तक पहुंच रही है। इस दौरान उन्होंने सरकारी एलिमेंटरी स्कूल पंडोरी खजूर में 7.51 लाख रुपए की लागत से बने नए क्लासरुम, सरकारी एलिमेंटरी स्कूल चक्कोवाल ब्राह्मणा में 7.51 लाख रुपए की लागत से बने क्लासरुम, सरकारी एलिमेंटरी स्कूल काठे अधिकारे में 4 लाख रुपए से बनी चारदीवारी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांधरा में 11 लाख रुपए से बनी आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला व इसी स्कूल में ही ढाई लाख रुपए की लागत के अन्य विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरुरतमंद और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वही आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्ता प्राप्त हो, जो निजी स्कूलों में मिलती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करे।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि नवनिर्मित कमरे स्मार्ट क्लास सुविधाओं और नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों से युक्त हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में प्रदेश में 118 स्कूल आफ एमीनेंस स्थापित किए गए हैं। अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जा रहा हैं ताकि बच्चों को आज के समय के हिसाब से बेहतरीन शिक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों में अध्यापकों की कमियों को दूर किया जा रहा है। अकेले होशियारपुर जिले में ही 600 नए अध्यापक दिए गए हैं, जिनमें से 125 विधान सभा शाम चौरासी के लिए भेजे गए हैं। डॉ. रवजोत सिंह ने इलाका वासियों से भी अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक संसाधनों का लाभ भी प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी (से) धीरज वशिष्ट, राजकुमार, ओंकार सिंह, संजीव कुमार, डा. विजय. सरपंच गुरमुख सिंह, बखशिंदर सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सरपंच संतोश सिंह, बलवीर सिंह, अनीश कुमार, जसवीर सिंह, कुलविंदर राम, शिंगारा सिंह, कुलवंत सिंह, सुखदेव, सतनाम सिंह, सरपंच अनिल कुमार, सरपंच बलजीत कौर, चंद्रमोहन वर्मा, सरपंच जसविंदर सिंह, निर्मल कौर, केवल सिंह, हरजिंदर सिंह के अलावा अन्य गणमान्य भी मौजूद थे।

सभी की सहभागिता से राजस्थान के हरित और उज्जवल भविष्य का होगा निर्माण : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी

एजेंसी (हि.स.)
जैसलमेर/जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। शर्मा गुरुवार को जैसलमेर के पोकरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं लेकिन सौर ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, यह अक्षय ऊर्जा है। हर परिवार सौर ऊर्जा का उत्पादक बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अभी तक अनेक कदम उठाए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान देश में सौर और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर है। सौर ऊर्जा के

पोकरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह किया संबोधित

क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 4 हजार 895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत एवं 41 हजार 883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार ने नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए छतों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए एक हजार मेगावाट क्षमता के पावर

फोटोः हि.स.

प्लांट हैम मॉडल के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6,311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादक कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं भी संचालित कर रही है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उनके पंचामृत लक्ष्यों का एक अहम हिस्सा है। यह लक्ष्य भारत के ऊर्जा भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा हमारे राष्ट्र की हरित ऊर्जा क्रांति का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही 4.5 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले छह गीगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उसे हासिल करने में राजस्थान महत्वपूर्ण योगदान देगा। शर्मा ने कहा कि आज शुरू हुआ यह संयंत्र मेक इन इंडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भारत में बने हुए 100 प्रतिशत मॉड्यूल इस्तेमाल हुए हैं और 90 प्रतिशत कंपोनेंट की खरीद राजस्थान से की गई है। यह बात स्थानीय उद्योगों के लिए अच्छी है तथा आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन के भी अनुरूप है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसे संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री का हैलीपेड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, विधायक महंत प्रतापपुरी, छोटू सिंह भाटी, रिन्यू के सीईओ सुमंत सिन्हा, अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

हिंदी देश की संपर्क भाषा है, सभी को सीखनी चाहिए : सीएम फडणवीस

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई में कहा कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है, इसलिए सभी को हिंदी सीखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी राज्य की भाषा है, इसलिए राज्य में रहने वाले सभी को मराठा आना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष से लागू की जा रही शिक्षा नीति कोई नई नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई नया सरकारी आदेश लागू नहीं किया गया है। शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का निर्णय व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य में हर किसी को मराठी आनी चाहिए। इसके साथ ही, आपको देश की भाषा भी बोलनी आनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस सोच के अनुरूप कि देश में संपर्क की एक ही भाषा होनी चाहिए। इसी वजह से शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य होगी।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी भाषा देश को जोड़ने वाली कड़ी है। इस शैक्षणिक वर्ष से नई शिक्षा नीति पहली कक्षा से लागू की जाएगी। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह नीति जून से लागू होगी। इसके अनुसार, राज्य ने कक्षा 1 से हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार, मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मराठी और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाएगी।

राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान हुआ बेनकाब: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि पड़ोसी देश कितनी भी कोशिश कर ले वैश्विक आतंकवाद के केन्द्र के रूप में उसकी छवि सुधर नहीं सकती। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण इसकी ताजा मिसाल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में कहा कि इससे यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान को मुंबई आतंकी हमले के जिम्मेदार अन्य लोगों, जिन्हें वह पनाह दे रहा है, उनको कानून के कटघरे में खड़ा करे। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के कश्मीर संबंधी बयान पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत का भूभाग पाकिस्तान की प्राण वाहिनी कैसे हो सकता है। कश्मीर भारत का संघीय भूभाग है। दोनों देशों के बीच केवल एक मुद्दा है कि पाकिस्तान भारत के उस भूभाग को खाली करे, जिसे उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

राजधानी में चार-पांच वर्षों में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाई देंगे : मनजिंदर सिंह सिरसा

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी में चार-पांच वर्षों में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाई देंगे। इसको खत्म करने के लिए सरकार दोगुनी रफ्तार से काम करेगी। इस क्रम में गुरुवार को मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में हर लैंडफिल साइट की निगरानी की जाएगी। लैंडफिल साइट पर कितना कचरा साफ हुआ और कितना अभी बाकी है। इसको हर दिन अपडेट किया जाएगा। इसका वास्तविक समय डेटा दिल्ली सरकार के डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली वालों को साफ पानी और हवा देने का जो वादा किया था, उसको पूरा करने की दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव के समय आपदा को खत्म करने के बाद अब यहां गंदगी को खत्म करना है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया।

फोटोः हि.स.

उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा रफ्तार को दोगुनी करने और नई एजेंसी को नियुक्त करने का भी कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए यह कूड़े के पहाड़ खतरा है। इनको खत्म करने की दिशा में दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर दिन लैंडफिल साइट पर कूड़े को साफ करने की निगरानी होगी।

मंत्री ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली जल्द ही दुनिया के अग्रणी शहरों में गिना जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली में हर वाहन की निगरानी की जाएगी। प्रत्येक वाहन कितना प्रदूषण फैलाता है, इसका वास्तविक समय डेटा दिल्ली सरकार के डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा।

संक्षिप्त-समाचार

सरकार ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बनाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बना दिया है। सरकार ने पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया है, जो 15 अप्रैल, 2025 से लागू हो गया है। कोयला मंत्रालय मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने और आयात निगरानी प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सीआईएमएस पोर्टल के पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है। यह पहले की शुल्क संरचना की जगह लेगा, जो प्रति खेप 500 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक थी। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और आयात निगरानी प्लेटफार्मों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। कोयला आयात निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करने के लिए एक अहम चरण के रूप में कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) को लागू किया है। उसने कहा कि कोयला आयात प्रतिस्थापन में वास्तविक समय की निगरानी और सूचित निर्णय लेने को सक्षम करके, यह पहल आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण चरण है। उल्लेखनीय है कि कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे कोयला आयात की रिपोर्टिंग को कारगर बनाने, प्रभावी नीति निर्माण और क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए समय पर और सटीक डेटा सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। पंजीकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से सीआईएमएस को इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस), अलौह आयात निगरानी प्रणाली (एनएफआईएमएस) और कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) जैसी समान आयात निगरानी प्रणालियों के साथ युक्तिसंगत किया गया है। यह सभी एक समान शुल्क मॉडल के तहत कार्य करती हैं।

गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने चार्ज संभाला

गाजियाबाद। गाजियाबाद के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों का परिचय लिया और उन्हें हिदायत दी कि वे दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ करें और जनहित में अपने कार्य को अंजाम दें। उन्होंने शासन कहा कि कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं रहेगा। 2005 मैच की आईपीएस जी रविंद्र गोड़ गुरुवार को गाजियाबाद पुलिस लाइन पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण किया। इससे पहले श्री गौड़ आगरा के पुलिस कमिश्नर पद पर तैनात थे। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से पहले कमिश्नर के रूप में पदारूढ़ अजय मिश्र ने ढाई साल से ज्यादा समय तक पद पर रहकर कीर्तिमान स्थापित किया। सख्त तेवरों और अभिनव प्रयोगों के रूप में उन्होंने गाजियाबाद पुलिस के स्वरूप को बदला। गौड़ आंध्र प्रदेश के महबूब नगर (वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश का हिस्सा है) वहां के मूल निवासी हैं। आईपीएस जे रविंदर कुमार की गिनती प्रदेश के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। आगरा में अपने 15 महीनों के कार्यकाल में पुलिस प्रणाली में अभिनव प्रयोग से शासन की भी वाहवाही लूटी। साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली लागू कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कवायद की थी। इसके लिए खुद पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी थी। इससे पहले वह जनपद गोरखपुर रेंज के आईजी सहित मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ समेत बड़े बड़े जिलों एसपी से लेकर डीआईजी और आईजी रह चुके हैं। इस मौके पर एडीसीपी कानून व्यवस्था कल्पना सक्सेना, डीसीपी सिटी राजेश कुमार, डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी तथा डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष दशरथ पाटिल समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

विश्व धरोहर दिवस पर एएसआई स्मारकों पर नहीं लगेगा कोई प्रवेश शुल्क

नई दिल्ली। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर देश के संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह जानकारी दी। 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य आगंतुकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। एएसआई द्वारा संरक्षित 3,698 स्मारकों और स्थलों में कई स्थानों पर प्रवेश शुल्क लिए जाते हैं। शुक्रवार को टिकट वाले सभी स्मारकों में प्रवेश निशुल्क होगा, जिसमें आगरा का ताजमहल सहित दिल्ली में लालकिला, सफदरजंग का मकबरा, कुतुबमीनार और पुराना किला शामिल है। गुरुवार को एएसआई द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष विश्व धरोहर दिवस का विषय 'आपदा एवं संघर्ष से खतरे में धरोहर' है, जिसके तहत प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, खतरों या संघर्षों से धरोहर स्थलों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। स्मारकों में प्रवेश शुल्क माफ करने का मकसद विरासत के संरक्षण और प्रबंधन के महत्व के बारे में अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरुक करना है ताकि अमूल्य विरासत स्थलों की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, तीर्थयात्रियों के लिए सूचना जल्द

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द ही दोबारा शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में जनता के लिए शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पिछली चीन यात्रा के दौरान दोनों देश विमान सेवा फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के तकनीकि दल विमान सेवाओं को बहाल करने के संबंध में विचार कर रहे हैं। दोनों देशों के नागर विमानन अधिकारियों की बैठक हुई है तथा उड़ान सेवाओं की नई रूपरेखा और औपचारिकताओं पर चर्चा हो रही है।

आर्य समाज मंदिर में वैदिक या अन्य हिन्दू रीति-रिवाजों से विवाह वैध: हाईकोर्ट

एजेंसी (हि.स.)
प्रयागराज

फोटोः हि.स.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में माना कि आर्य समाज मंदिर में दो हिन्दुओं (पुरुष और महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं। यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिन्दू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार किए गए हों। और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर, घर या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में विवाह वैदिक पद्धति के अनुसार सम्पन्न होते हैं। जिसमें कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदी तथा सिंदूर लगाते समय मंत्रोच्चार जैसे हिन्दू रीति-रिवाज और संस्कार शामिल होते हैं। ये समारोह 1955 अधिनियम की धारा 7 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र में विवाह की प्रथम दृष्टया वैधता का वैधानिक बल नहीं हो सकता है, फिर भी ऐसे प्रमाण पत्र 'बेकार कागज' नहीं हैं। क्योंकि उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार पुरोहित (जिसने विवाह सम्पन्न कराया था) द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

इस आदेश के साथ एकल न्यायाधीश ने महाराज सिंह नामक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दायर मामले को रद्द करने की मांग की थी। एसीजेएम बरेली की कोर्ट में चल रही आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई थी। आवेदक ने न्यायालय में तर्क दिया कि चूंकि उसका कथित विवाह विपक्षी संख्या 2 के साथ आर्य समाज मंदिर में हुआ था, इसलिए उसे वैध विवाह नहीं माना जा सकता। इसलिए, उसे धारा 498-ए आईपीसी के तहत आरोपों का सामना करने का अधिकार नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि वास्तव में आर्य समाज मंदिर में कोई विवाह नहीं हुआ था तथा उनकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाणपत्र, जिसे कथित रूप से आर्य समाज द्वारा जारी किया गया था, जाली एवं मनगढ़ंत था।

रंगदारी के लिए गैंगस्टर ने पतरातू में चलवाई पांच राउंड गोली

रामगढ़। रामगढ़ जिले में गैंगस्टर राहुल दुबे का गैंग लगातार दहशत फैलाने का काम कर रहा है। लेवी की रकम वसूलने के लिए कोलियरी को उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सिरका कोलियरी के बाद पतरातू गुड्स सेट दामोदर मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड के कोयला एंट्री गेट पर पांच राउंड फायरिंग कराई गई। इस फायरिंग की जिम्मेदारी अपराधी राहुल दुबे ने ली और इसे एक ट्रेलर बताया है।घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार को पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटनास्थल से पुलिस ने खोखे भी बरामद किए हैं। कोयला एंट्री गेट चेक पोस्ट पर मौजूद कर्मियों ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात दो अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन लोगों ने बताया कि बुलेट पर सवार दो लोग चेक पोस्ट के पास पहुंचे। एक व्यक्ति बाइक पर ही मौजूद रहा और दूसरा उतरकर गोली चलाने लगा। दो गोली चेक पोस्ट के अंदर चलाई और तीन गोली चेक पोस्ट के बाहर चलाई गई। इसके बाद वे लोग पर्चा फेक कर फरार हो गए।

काठमांडू में दो करोड़ के अवैध सोने- चांदी के गहने सहित नौ भारतीय गिरफ्तार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल के काठमांडू से दो करोड़ रुपये से अधिक के सोने और चांदी के गहने सहित नौ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह राजधानी के विभिन्न स्थानों सोना और चांदी की अवैध बिक्री कर रहे थे।

काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता अपील बोहरा कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान छापा मार कर एक किलो 76.518 ग्राम सोना तथा एक किलो 845.429 ग्राम चांदी जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने की कीमत एक करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि चांदी की कीमत 30 लाख रुपये है। इसके अलावा उनके कब्जे से 8 लाख 27 हजार रुपये नेपाली करेंसी और 91 हजार 700 रुपये भारतीय करेंसी बरामद की गई है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में 30 वर्षीय नव नाथ बाकू कासिद, संदीप पोपट हजारे 20 वर्ष, अंसार दिलावर सिकलगर 22 वर्ष, सुरेश राजेश मदने 18 वर्ष, अरमान हनीफ इमांडया 21 वर्ष, मनोज सुभाष सकत 22 वर्ष, अमोल कुमार गोस्ले 38 वर्ष, सुनील मितकारी 20 वर्ष और सूरज नंदीवाली 20 वर्ष शामिल हैं।

दलित वोटों के स्वार्थ की खातिर सपा किसी भी हद तक जा सकती है: मायावती

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

फोटोः हि.स.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ-साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर सपा के राजनीतिक हथकण्डों का शिकार होने से बचना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को कहा कि सभी को पता है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा किया जा रहा है। इनकी अति विवादित बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है। यह इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका-टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाईयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा। उन महारुषों के कारण ये लोग किसी लायक बने हैं।

'स्वागत एवं अभिनन्दन' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत

राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलोजी के माध्यम से पारदर्शिता लाई गई: धामी

एजेंसी (हि.स.
देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलजी के माध्यम से पारदर्शिता लाने का कार्य किया गया है। राज्य में इकॉनोमी और इकॉलोजी के बीच समन्वय बनाकर ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की ओर से आयोजित 'स्वागत एवं अभिनन्दन' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभिनंदन की असली हकदार उत्तराखंड प्रदेश की जनता है, जिन्होंने प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पॉवर सरप्लस राज्य बनाने के लिए सबको समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार का राज्य सरकार को हर योजना पर सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। बिजली उत्पादन के लिए लखवाड़ बांध परियोजना, जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और देहरादून में आने वाले 50 सालों में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर कार्य गतिमान है। राज्य में अत्याधुनिक जीआईएस (गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन) उपकेंद्रों की स्थापना भी जारी है। उन्होंने कहा राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलजी के माध्यम से पारदर्शिता लाने का कार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून शहर की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही हैं। यूपीसीएल की ओर से अत्याधुनिक ओटोमेटेड डिमान्ड रिसपॉन्स सिस्टम के उपयोग से ओवरड्राल की स्थिति पर रियल टाइम पर नियंत्रण कर हर वर्ष करोड़ो रुपए की बचत की है। उन्होंने कहा कि 2023 में देहरादून में विश्व स्तरीय आपदा प्रबंधन सम्मलेन आयोजित किया गया था। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता पर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता लहै। राज्य सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन वाले विकास के मॉडल को चुना है। इकॉनमी और इकॉलजी के बीच समन्वय बनाकर ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को हमने अपने राज्य में भी अपनाना है।

बायर्न म्यूनिख को 4-3 से हराकर इंटर मिलान चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में

लौटारो और पावार्ड के गोल ने इंटर को दिलाई बढ़त

डायर ने दिलाई उम्मीद, लेकिन समर ने बचाई जीत

एजेंसी (हि.स.)

मिलान

फोटोः हि.स.

इंटर मिलान ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 के क्वार्टरफाइनल के रोमांचक मुकाबले में बायर्न म्यूनिख को 4-3 के एग्रीगेट स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार देर रात सान सिरो स्टेडियम में हुए दूसरे लेग का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन पहले लेग में मिली 2-1 की जीत के चलते इटालियन चैंपियन इंटर ने अंतिम-4 में प्रवेश किया। अब इंटर का मुकाबला सेमीफाइनल में बार्सिलोना से होगा।

बारिश और तेज हवाओं के बीच खेले गए इस मुकाबले में पहले हाफ तक दोनों टीमों के बीच गोल नहीं हुआ। हालांकि, दूसरे हाफ में मुकाबला रोमांचक हो उठा। बायर्न के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने 52वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया और मुकाबले को नई जान दे दी। इसके बाद इंटर के कप्तान लौटारो मार्टिनेज ने 58वें मिनट में गोल दागकर इंटर को फिर से बढ़त दिलाई। महज तीन मिनट बाद, बेंजामिन पावार्ड ने एक शानदार हेडर से गोल कर इंटर को निर्णायक बढ़त दिला दी।

75वें मिनट में एरिक डायर ने बायर्न के लिए हेडर के जरिए गोल कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। इसके बाद बायर्न ने बराबरी के लिए लगातार दबाव बनाया। स्टॉपेज टाइम में हैरी केन का हेडर इंटर के गोलकीपर यान समर ने शानदार तरीके से रोक लिया और यहीं से इंटर की जीत तय हो गई।

इंटर मिलान के फैंस ने टिकट की बढ़ी कीमतों के विरोध में शुरूआती 20 मिनट तक स्टेडियम में सन्नाटा बनाए रखा। इसके बाद फैंस ने जोरदार शोर और गानों से अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। इंटर अब 2010 के जोसे मोरिन्हो युग की तरह एक बार फिर से सीरी ए, चैंपियंस लीग और इटालियन कप ट्रेबल जीतने की ओर बढ़ रही है। टीम इस समय इटली की लीग टेबल में नेपोली से तीन अंकों की बढ़त बनाए हुए है और डोमेस्टिक कप के सेमीफाइनल में एसी मिलान से भिड़ने वाली है।

आर्सेनल 16 साल बाद चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में

मैड्रिड। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने चैंपियंस लीग 2024-25 सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड को क्वार्टरफाइनल में 5-1 के एग्रीगेट स्कोर से मात दी। बुधवार रात हुए दूसरे लेग के मुकाबले में आर्सेनल ने 2-1 से जीत दर्ज कर 16 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) से होगा। आर्सेनल ने पिछले हफ्ते लंदन में खेले गए पहले लेग में 3-0 की बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसका फायदा उन्हें मैड्रिड में मिला। मैच की शुरूआत से ही आर्सेनल ने रक्षात्मक रणनीति अपनाई और रियल मैड्रिड के आक्रामक खेल को ज्यादा मौके नहीं दिए। पहले हाफ में आर्सेनल को पेनल्टी का मौका मिला जब वीएआर की मदद से रियल के राउल असेंसियो द्वारा मिकेल मेरिनो को खींचने का मामला पकड़ में आया। हालांकि, साका का पेनल्टी किक थिबो कोर्टुआ ने रोक लिया। इस चूक के बाद साका ने दूसरे हाफ में 65वें मिनट में शानदार वापसी की और टीम के लिए पहला गोल दागा। साका के गोल के दो मिनट बाद ही विलियम सलीबा की गलती का फायदा उठाते हुए विनीसियस जूनियर ने बराबरी का गोल कर रियल को थोड़ी उम्मीद दी। लेकिन, स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे के चोटिल होकर मैदान छोड़ने से रियल मैड्रिड की मुश्किलें और बढ़ गईं।

आईपीएल 2025 में पहली बार सपोर्ट स्टाफ पर लगा जुमार्ना

दिल्ली कैपिटल्स के कोच मुनाफ पटेल पर हुई कार्रवाई

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में एक नया मामला सामने आया है, जब पहली बार किसी टीम के सपोर्ट स्टाफ सदस्य पर आचार संहिता के उल्लंघन के चलते जुमार्ना लगाया गया है। बुधवार (16 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दिल्ली के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल पर कार्रवाई की है। आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुनाफ पटेल ने 'लेवल 1' के तहत अनुच्छेद 2.20 का उल्लंघन किया, जो खेल की भावना के खिलाफ आचरण से जुड़ा है। मुनाफ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और मैच रेफरी के फैसले को मान लिया है। इसके चलते उनकी 25 प्रतिशत मैच फीस काटी गई और एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया। हालांकि, आईपीएल ने इस मामले का ब्योरा नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक मुनाफ की चौथे अंपायर से एक रणनीतिक संदेश मैदान में भेजने को लेकर गर्मागर्म बहस हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह इस सीजन का दूसरा अनुशासनात्मक मामला है। इससे पहले कप्तान अक्षर पटेल पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया था। बुधवार का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमें 188 रन बनाकर बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान को सिर्फ 11 रन पर रोक दिया। इसके बाद केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने महज 4 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर टीम को जीत दिलाई। जीत के बाद दिल्ली के डगआउट में जश्न का माहौल था। मुनाफ पटेल, हेमांग बदानी और केविन पीटरसन समेत कोचिंग स्टाफ ने एक-दूसरे को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं, राजस्थान के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ सहित पूरा कैंप मायूस नजर आया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने छह में से पांच मैच जीतकर 10 अंकों के साथ अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। वे इस सीजन 10 अंक तक पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।

ज्वाला देवी गंगापुरी के दो छात्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चयनित

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

प्रयागराज

विद्या भारती से सम्बद्ध ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुरी रसूलाबाद के छात्रों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ है। अब दोनों खिलाड़ी बिहार राज्य के पांच शहरों में 4 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य युगल किशोर मिश्र ने गुरुवार को बताया कि झारखण्ड के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी रांची में विद्या भारती द्वारा आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुरी रसूलाबाद के छात्र आर्य देव ने पोल वाल्ट में गोल्ड मेडल तथा शहंशाह ने जैवलिन में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। जिनका चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हुआ है। दोनों खिलाड़ियों के चयनित होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य युगल किशोर मिश्र, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉ.राम मनोहर, विद्या भारती क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख जगदीश कुमार सिंह, विद्यालय प्रबंधक राकेश सिंह सेंगर, अध्यक्ष च्यवन भार्गव एवं विद्यालय के शारीरिक शिक्षक शिव कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।

डे क्रिकेट अकादमी के लिए 20 अप्रैल को ट्रायल

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए द्वारा अंडर-19 डे क्रिकेट अकादमी धर्मशाला के लिए 20 अप्रैल को ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान वर्ष 2025-26 के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ट्रायल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे से होंगे। ट्रायल में पूर्व वर्ष में चयनित खिलाड़ियों को भी भाग लेना होगा, उनकी प्रतिभा के तहत ही उन्हें आगामी वर्ष के लिए रिटेन किया जाएगा। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का जन्म एक सितंबर 2006 के बाद होना जरूरी है। साथ ही मात्र हिमाचली बोनोफाईड खिलाड़ी ही ट्रायल में भाग ले सकेंगे। इसके लिए खिलाड़ियों को ट्रायल वाले दिन ही रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। बिना पंजीकरण के ट्रायल में खिलाड़ी भाग नहीं ले पाएंगे। इसके लिए खिलाड़ियों को जन्मतिथि प्रमाण पत्र, बोनोफाईड हिमाचली व दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लाने होंगे। अवनीश परमार ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का अलांउस प्रदान नहीं किया जाएगा।

नीरज चोपड़ा ने पोटचेफस्ट्रूम आमंत्रण टूर्नामेंट में 84.52 मीटर थ्रो के साथ जीता स्वर्ण

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

डबल ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में पोटचेफस्ट्रूम इनविटेशनल में 84.52 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ अपने 2025 सीजन की शुरूआत की। उनके इस प्रदर्शन ने विश्व एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण वर्ष में छह पुरुषों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। चोपड़ा 25 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी भाला फेंक खिलाड़ी डौ स्मिट से काफी आगे रहे, जिन्होंने 82.44 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया। भारतीय स्टार ने शुरूआती सीजन में कुछ मजबूत थ्रो किए, जिसमें सिर्फ.वह और स्मिट ही 80 मीटर का आंकड़ा पार कर पाए। तीसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो स्थानीय एथलीट डंकन रॉबर्टसन का रहा, जिन्होंने 71.22 मीटर तक थ्रो किया। हालांकि, नीरज का थ्रो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर से कम था, लेकिन यह एक ठोस शुरूआत थी, जबकि स्मित 83.29 मीटर के अपने ही मार्क के करीब पहुंच गए। नीरज का अगला बड़ा इवेंट 16 मई को दोहा डायमंड लीग है, जहां उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज ने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता था, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, सभी की निगाहें नीरज पर होंगी कि क्या वह नदीम के रिकॉर्ड को चुनौती देकर अपने पहले से ही शानदार करियर को आगे बढ़ा सकते हैं।

सुरुचि-सौरभ की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण

नई दिल्ली। लीमा (पेरू) में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बुधवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक मुकाबले में सुरुचि-सौरभ की जोड़ी ने चीन की कियानसुन याओ और काई हू की जोड़ी को 17-9 के अंतर से पराजित किया। दोनों भारतीय निशानेबाजों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य भेदा और खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत की मनु भाकर और रविंदर सिंह की जोड़ी को चीनी निशानेबाजों चियानके मा और यीफान झांग के हाथों 6-16 से हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को 18 वर्षीय सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रायजा पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचीं, पांचवें स्थान पर रहीं

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

पेरिस ओलंपियन रायजा ढिल्लों ने अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए स्कीट महिला इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और पांचवें स्थान पर रहीं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन के दूसरे चरण के दूसरे दिन भारत ने दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ चीन के बाद कुल तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। पूर्व जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट और पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य जीतने वाली रायजा ने बुधवार को अपने पहले सीनियर वर्ल्ड कप फाइनल में मजबूत प्रदर्शन किया। 60 शॉट के फाइनल में उन्होंने 30 शॉट्स के बाद 26 हिट किए और बाहर हो गईं। उन्हें चीन की जियांग यीटिंग को पछाड़ना था, जो पेरिस ओलंपिक में मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। रायजा को उच्चतम बिब नंबर का नुकसान भी झेलना पड़ा। उन्होंने पहले 20 में से 19 शॉट्स हिट किए, जिससे दूसरी चीनी फाइनलिस्ट चे यूफेई को पीछे छोड़ने में कामयाब रहीं। शॉटगन की दिग्गज और तीन बार की ओलंपिक चैंपियन किम्बरली रोड ने 56 हिट्स के साथ स्वर्ण पदक जीता, और अमेरिकी टीम ने इस इवेंट में 1-2-3 स्थान हासिल किया। सामंथा साइमोंटन को स्वर्ण के लिए शूट-ऑफ में रोड से 1-2 से हारकर रजत से संतोष करना पड़ा, जबकि पूर्व विश्व चैंपियन डानिया जो विजी ने कांस्य पदक जीता।

आहार के नियम भारतीय 12 महीनों के अनुसार

चैत्र	(मार्च-अप्रैल):-	इस महीने में चने का सेवन करे क्योकि चना आपके रक्त संचार और रक्त को शुद्ध करता है एवं कई बीमारियों से भी बचाता है। चैत्र के महीने में नित्य नीम की 4 झ 5 कोमल पतियों का उपयोग भी करना चाहिए इससे आप इस महीने के सभी दोषों से बच सकते है। नीम की पतियों को चबाने से शरीर में स्थित दोष शरीर से हटते है।
वैशाख	(अप्रैल-मई):-	वैशाख महीने में गर्मी की शुरूआत हो जाती है। बेल का इस्तेमाल इस महीने में अवश्य करना चाहिए जो आपको स्वस्थ रखेगा। वैशाख के महीने में तेल का उपयोग बिल्कुल न करे क्योकि इससे आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है।
ज्येष्ठ	(मई-जून):-	भारत में इस महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में सोना स्वास्थ्य वर्द्धक होता है , ठंडी छाछ, लस्सी, ज्यूस और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। बासी खाना, गरिष्ठ भोजन एवं गर्म चीजो का सेवन न करे। इनके प्रयोग से आपका शरीर रोग ग्रस्त हो सकता है।
अषाढ़	(जून-जुलाई):-	आषाढ़ के महीने में आम , पुराने गेंहू, सत्तु , जौ, भात, खीर, ठन्डे पदार्थ , ककड़ी, पलवल, करेला, बथुआ आदि का उपयोग करे व आषाढ़ के महीने में भी गर्म प्रकृति की चीजों का प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
श्रावण	(जूलाई-अगस्त):-	श्रावण के महीने में हरड का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रावण में हरी सब्जियों का त्याग करे एव दूध का इस्तेमाल भी कम करे। भोजन की मात्रा भी कम ले झ पुराने चावल, पुराने गेंहू, खिचड़ी, दही एवं हलके सुपाच्य भोजन को अपनाएं।
भाद्रपद	(अगस्त-सितम्बर):-	इस महीने में हलके सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल कर वर्षा का मौसम्होने के कारण आपकी जठराग्नि भी मंद होती है इसलिए भोजन सुपाच्य ग्रहण करे। इस महीने में चिता औषधि का सेवन करना चाहिए।
आश्विन	(सितम्बर-अक्टूबर):-	इस महीने में दूध , घी, गुड़ , नारियल, मुन्नका, गोभी आदि का सेवन कर सकते है। ये गरिष्ठ भोजन है लेकिन फिर भी इस महीने में पच जाते है क्योकि इस महीने में हमारी जठराग्नि तेज होती है।
कार्तिक	(अक्टूबर-नवम्बर):-	कार्तिक महीने में गरम दूध, गुड, घी, शक्कर, मुली आदि का उपयोग करे। ठंडे पेय पदार्थो का प्रयोग छोड़ दे। छाछ, लस्सी, ठंडा दही, ठंडा फ्रूट ज्यूस आदि का सेवन न करे , इनसे आपके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है।
अगहन	(नवम्बर-दिसम्बर):-	इस महीने में ठंडी और अधिक गरम वस्तुओ का प्रयोग न करे।
पौष	(दिसम्बर-जनवरी):-	इस ऋतु में दूध, खोया एवं खोये से बने पदार्थ, गौंद के लाडू, गुड़, तिल, घी, आलू, आंवला आदि का प्रयोग करे, ये पदार्थ आपके शरीर को स्वास्थ्य देंगे। ठन्डे पदार्थ, पुराना अन्न, मोठ, कटु और रुक्ष भोजन का उपयोग न करे।
माघ	(जनवरी-फरवरी):-	इस महीने में भी आप गरम और गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल कर सकते है। घी, नए अन्न, गौंद के लड्डू आदि का प्रयोग कर सकते है।
फाल्गुन	(फरवरी-मार्च):-	इस महीने में गुड का उपयोग करे। सुबह के समय योग एवं स्नान का नियम बना ले। चनेकोउपयोगेनेकरे।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ दो दिवसीय वर्चुअलएक्स शिखर सम्मेलन

आज हांगी उत्तर क्षेत्र की डब्ल्यूएएफएक्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा

संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में गुरुवार 17 अप्रैल को विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एनिमेशन के विविध पहलुओं पर दो दिवसीय वर्चुअलएक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। शिखर सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के एनीमेशन विभाग द्वारा वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार तथा एबीएआई (बैंगलोर एनीमेशन उद्योग संघ) के सहयोग से किया जा रहा है।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने और सरकार की 'क्रिएट इन इंडिया' पहल का समर्थन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और एबीएआई द्वारा आयोजित किए जा रहे

- क्षेत्रीय विजेता वेव्स-2025 में 24 घंटे में चुनौती से निपटने की प्रतिस्पर्धा करेंगे।

डब्ल्यूएएफएक्स, वेव्स व वीएफएक्स चैलेंज की क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर क्षेत्र भागीदार के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है।

शिखर सम्मेलन के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, उनमें बहुप्रतिक्षित एनिमेटेड फीचर फिल्म 'छावा' के निर्माण के पीछे की अंतर्दृष्टि, साथ ही नेटफ्लिक्स की आगामी एनिमेटेड फिल्म 'वुल्फ किंग' भी शामिल है। कार्यक्रम में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, विजुअल इफेक्ट्स और विस्तारित वास्तविकता (एक्सटेंडिट रियलिटी एप्लीकेशन) अनुप्रयोगों में अत्याधुनिक विकास को

भी शामिल किया गया है, जो क्रिएटिव टेक्नालोजी क्षेत्र में छात्रों और विशेषज्ञों (प्रोफेशनल्स) को मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा।

शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विभागाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक प्रो. पामिल अरोड़ा और श्री अजयपाल सिंह चन्ना ने किया तथा उद्योग जगत के कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन भाषण में कुलपति (शैक्षणिक मामले) प्रो. डॉ. वी.आर. रघुवीर ने विद्यार्थियों को बताया कि विश्वविद्यालय उन्हें एक ऐसा वातावरण देने का प्रयास करता है, जहां विद्यार्थी प्रयोग कर सकें, नई चीजों को सीख सकें और यदि कहीं कठिनाई आए तो उसका सामना करने साथ, वे भविष्य के लिए तैयार रहें।

द मिल के कार्यकारी निदेशक श्री चंद आरके, एबीएआई के अध्यक्ष श्री बीरेन घोष, पिक्सेल एंड रशियो के संस्थापक और क्रिएटिव निदेशक श्री अनिरबनदीप दत्ता, जेबू एनिमेशन के निदेशक श्री वीरेन पटेल, क्राफ्टन के कला निदेशक श्री श्याम देशपांडे और द मिल के क्रिएटिव विभाग के प्रमुख श्री राकेश वेणुगोपालन ने भी छात्रों और अन्य शिखर सम्मेलन प्रतिभागियों के साथ रोचक पहलु और दृष्टिकोण साझा किए। उत्तर क्षेत्र की डब्ल्यूएएफएक्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी और अतिथियों द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्रीय विजेता वेव्स-2025 में 24 घंटे में चुनौती से निपटने की प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगी वीएफएक्स शॉट बनाने के लिए हरे मैट स्क्रीन, 3डी एसेट्स और एफएक्स लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे। प्रत्येक श्रेणी में चैम्पियन को नकद पुरस्कार और विशेष उपहार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन 18 अप्रैल शुक्रवार को भी जारी रहेगा, जिसमें दृश्य प्रभाव, एनीमेशन और गेमिंग पर आगे के सत्र होंगे।

उपायुक्त ने पेयजल समस्या की जांच कर जल्द कार्य शुरू करने के दिए निर्देश

- जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की

संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में थापली गांव में पेयजल की समस्या पर संज्ञान लेते हुए पब्लिक हैल्थ को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सोमवार व वीरवार को जिला में प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता की समस्याओं का मौके पर व जल्द से जल्द समाधान करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी स्वयं शिविर से जुड़ते है व शिविरों में सुनी जा रही समस्याओं की मोनिटरिंग करते है।

उपायुक्त ने अभयपुर के पार्षद राजेश कुमार की आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में पांचवी तक अंग्रेजी पढ़ाने व पांचवी से आठवीं तक अंग्रेजी न पढ़ाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने नाडा साहब गांव के केसर सिंह की मकान के आगे डंगे लगवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को मोके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। उन्होंने आज समाधान शिविर में 16 जिलावासियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कालका एसडीएम कार्यालय, नगर निगम पंचकूला कार्यालय में भी समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है, जिलावासी अपनी नगर निगम से संबंधित शिकायतों को उनके कार्यालय जाकर समस्याओं का समाधान करवा सकते है।

उपायुक्त ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी यहां जिलावासियों की समस्याओं के समाधान के लिए एकत्रित हुए है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले की जनता को बार बार अपने कार्यो के लिए चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इसमें किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय कालका में भाषण प्रतियोगिता आयोजित

संवाददाता
कालका

राजकीय महाविद्यालय कालका की प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा के कुशल नेतृत्व में सेलिब्रेशन आफ डेज कमेटी और लोक प्रशासन विभाग के सौजन्य से भाषण प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता का विषय बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन और विचार, माता अहिल्याबाई होलकर रहा। विद्यार्थियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार प्रस्तुत किए की जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो, मनुष्य महान बनता है अपने कर्मों से ना की जन्म से। भाषण प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा बीए द्वितीय वर्ष की शबाना प्रथम स्थान पर रही, एमकॉम द्वितीय वर्ष की कनू प्रिया द्वितीय स्थान पर रही, बी.ए. द्वितीय वर्ष की हर्ष प्रिया तृतीय स्थान पर रही, बीए प्रथम वर्ष की तनिका और एम. ए. हिंदी प्रथम वर्ष की काजल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। निर्णायक मंडल की सदस्या प्रोफेसर डॉ बिंदु, प्रोफेसर नीतू, असिस्टेंट प्रोफेसर सविता रही। प्रस्तुत कार्यक्रम सेलिब्रेशन आफ डेज कमेटी की प्रभारी प्रोफेसर नीतू चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर बिंदु, डॉ प्रदीप, प्रोफेसर डॉ बिंदु रानी, डॉ सोनाली, डॉ नमिता और लोक प्रशासन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सविता के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में किया गया।

एसीबी ने तीन हजार रिश्वत लेते एक को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़। एसीबी की फरीदाबाद टीम द्वारा दिनांक 17.4.2025 को आरोपी धर्मेन्द्र क्लर्क-कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय बी.डी.पी.ओ. होडल जिला पलवल हाल अस्थाई डियुटी कार्यालय मार्केट कमेटी, अनाज मण्डी, हसनपुर जिला पलवल के कहने पर उसके साथी योगेश कुमार निवासी गांव जवां जिला फरीदाबाद द्वारा (प्राईवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से 3,000/-रुपए (तीन हजार रुपए) नगद बतौर रिश्वत राशी लेते हुये कार्यालय मार्केट कमेटी, अनाज मण्डी हसनपुर, जिला पलवल से रंगे हाथो गिरफतार किया गया है तथा मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र क्लर्क को भी अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गिरफतार किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 10 दिनांक 17.4.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में दर्ज किया गया है।

चंडीगढ़ सेक्टर-15 में पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण अभियान में भारी भीड़

संवाददाता
चंडीगढ़

उद्योग विभाग, यूटी चंडीगढ़ ने नगर निगम पार्षद सौरभ जोशी के सहयोग से आज सेक्टर 15 स्थित सामुदायिक केंद्र में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य योजना के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। शिविर के दौरान पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े सैकड़ों कारीगरों ने पंजीकरण कराया, जिसमें माला बनाने वाले, धातु बनाने वाले, मोची, कुम्हार और हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले कारीगर शामिल थे। यह योजना के उद्देश्यों में समुदाय की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। यूटी चंडीगढ़ के उद्योग विभाग के निदेशक पवित्र सिंह ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद

सौरभ जोशी के साथ मिलकर कारीगरों से बातचीत की और उनके कौशल विकास और पंजीकरण में सहायता के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित करने के महत्व पर जोर देते हुए, सौरभ जोशी ने शिविर के लिए लाभार्थियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चंडीगढ़ मजदूर सेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने के लिए यशपाल जिंदल, चरणजीत सिंह, विनय सचदेवा, दौलत शर्मा, सुरेश कटोच, श्रीनिवास और राजा का भी आभार व्यक्त किया। जोशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चंडीगढ़ में पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मजबूत सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। उद्योग विभाग के अधिकारी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने, पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता करने और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौजूद थे। विभाग ने पारंपरिक शिल्प और आजीविका को संरक्षित करते हुए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और औपचारिक एकीकरण के माध्यम से कारीगरों और कुशल श्रमिकों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

संक्षिप्त-समाचार

सुप्रकाश अधिकारी ने एनएचपीसी के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया

चंडीगढ़। सुप्रकाश अधिकारी ने वीरवार को भारत की अग्रणी जलविद्युत कंपनी और भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले, श्री सुप्रकाश अधिकारी, एनएचपीसी में कार्यपालक निदेशक (ओ एंड एम) के पद पर कार्यरत थे। अधिकारी ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पूर्व नामः बी.ई. कॉलेज), शिवपुर, पश्चिम बंगाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एनएचपीसी में अपने प्रोफेशनल कैरियर का प्रारम्भ दिसंबर 1990 में गुणवत्ता आश्वासन विभाग, एनएचपीसी निगम मुख्यालय में प्रशिक्षु कार्यपालक (इलेक्ट्रिकल) के रूप में किया। सुप्रकाश अधिकारी के पास परियोजना की संकल्पना से लेकर चालू करने तक के सभी चरणों के साथ-साथ प्रचालन और अनुरक्षण के कार्यों सहित जलविद्युत क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का विशिष्ट अनुभव है। एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पहले, उन्होंने ओएंडएम और सेफ्टी विभाग के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने प्रमुख प्रचालन उत्कृष्टता पहलों का नेतृत्व, विनियामक अनुपालन में सुधार और ईष्टतम अनुरक्षण कार्यक्रमों को संपादित किया - जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड वार्षिक विद्युत उत्पादन, उच्चतम संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) और अघोषित विद्युत कटौती में महत्वपूर्ण कमी हुई। अधिकारी ने डिजाइन (ई एंड एम) विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला, जहां उनकी तकनीकी विशेषज्ञता एनएचपीसी और इसकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में जलविद्युत और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए ई एंड एम पैकेजों की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण थी। उनकी निष्ठा और नेतृत्व ने 800 मेगावाट की पार्बती-क्क्र जल विद्युत परियोजना के सफल कमीशनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 540 मेगावाट चमेरा-क्, 120 मेगावाट सेवा-क्क्र, 45 मेगावाट निम्मो बाजगो, 132 मेगावाट टीएलडी-क्क्क और 60 मेगावाट रंगीत सहित प्रमुख पावर स्टेशनों के परियोजना प्रमुख के रूप में श्री अधिकारी ने प्रचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करते हुए महत्वपूर्ण तकनीकी मुद्दों का समाधान किया। सेवा-क्क्र में उन्होंने क्षतिग्रस्त हेड रेस सुरंग को निर्धारित समय से पहले पुनः चालू करवाने के कार्य का नेतृत्व किया - जो एक प्रमुख इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। अधिकारी ने अध्ययन और आधिकारिक कार्यों के लिए फ्रांस, नॉर्वे और यूक्रेन सहित कई देशों का दौरा किया है।

डिप्टी मेयर ने नगर निगम की हाउस टैक्स कमेटी से दिया इस्तीफा

चंडीगढ़। कांग्रेस नेता व डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने नगर निगम की हाउस टैक्स कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। वह कमेटी की मेंबर थीं। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में तरुणा मेहता ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने और चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। मेहता ने कहा कि, जब शहर में 3 गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया हो तो ऐसे में अब इस कमेटी का और मीटिंग करने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। तरुणा मेहता ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि मेयर हरप्रीत कौर द्वारा नगर निगम हाउस की मीटिंग में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का एजेंडा लाने से पहले इस हाउस टैक्स कमेटी में इस पर डिस्कशन क्यों नहीं की गई? मेहता आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक सोची-समझी साजिश के तहत हाउस टैक्स कमेटी को नजरअंदाज किया और सीधे मेयर के जरिए टैक्स बढ़ाने का एजेंडा हाउस में लाकर फिर उसे जानबूझकर रिजेक्ट करवाया। इससे प्रशासन के लिए कानूनी तौर पर रास्ता साफ किया गया। ताकि प्रशासन खुद अपनी मनमर्जी से टैक्स बढ़ा सके और लागू कर सके। मेहता ने कहा कि प्रशासन के आगे बेबस और लाचार मेयर और भाजपा के पार्षदों द्वारा इस्तीफे की धमकी देना ये साबित करता है कि आज केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन आने वाले प्रशासन के अधिकारी भाजपा की नहीं सुनते हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं, जोकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है।

पोषण अभियान के तहत पोषण जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित

संवाददाता

आईटी स्नातकों के लिए रोजगार मेला आयोजित

संवाददाता
चंडीगढ़

वीरवार को रोजगार कार्यालय विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में रोजगार मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

आईटी स्ट्रीम (बीसीए, बीएससी आईटी, बीए आईटी, एमएससी आईटी) के स्नातकों के लिए विशेष रूप से आयोजित इस रोजगार मेले का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटना और युवा पेशेवरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस आयोजन के लिए कुल 322 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया और 17 प्रतिष्ठित कंपनियों- जिनमें फिनवर्स, ब्लू बैश, जीएमआई इंफ्रा, ज्यूपिटिस और नर्व सेल शामिल हैं- ने साक्षात्कार आयोजित किए। भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप, 118 उम्मीदवारों को नौकरी के प्रस्तावों के लिए चुना गया, जो युवा रोजगार और

कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दीप्रवा लाकड़ा, सचिव वित्त-सह-श्रम एवं रोजगार; नितीश सिंगला, निदेशक आईटी; तथा संयुक्त सचिव श्रम एवं रोजगार-सह-आरईओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा नियोक्ताओं और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

यह कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप योजनाओं (एनएपीएस और एनएटीएस) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम आया। आउटरीच और जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर लाभ उठाया गया।

यह रोजगार मेला शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सफल तालमेल को दशार्ता है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर और कौशल वृद्धि के अवसरों के साथ सशक्त बनाकर कौशल भारत मिशन के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर विहिप ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भेंट कर भारत के राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में तत्काल हस्तक्षेप कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में विहिप पंजाब के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, महासचिव सुनील दत्त, उप महासचिव प्रशांत जोशी और संपर्क प्रमुख प्रदीप शर्मा शामिल थे। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित अन्य जिलों में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को रेखांकित किया गया है, जहां हाल ही की हिंसक घटनाओं में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों का हवाला देते हुए, विहिप ने राज्य प्रशासन की विफलता की कड़ी निंदा की है और कहा है कि प्रशासन सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा है। विहिप ने अपने ज्ञापन में पश्चिम बंगाल सरकार की कथित उदासीनता और तुष्टिकरण की राजनीति की कड़ी आलोचना की।

ज्ञानचंद गुप्ता ने भरैली में नलकूप के कार्य का किया शुभारंभ

संवाददाता
बरवाला

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 24, 25 के पूल के उदघाटन अवसर पर मुख्यमंत्री की रैली के लिए पंचकूला विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया और सभी कार्यकताओं व गांववासियों को रैली में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। गांवों में दौरे के दौरान ही ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव भरेली में 18 लाख रुपए की लागत से लगने जा रहे पानी के नए नलकूप का शिलान्यास किया व नयागांव में 15 लाख रुपए की लागत से होने जा रहे तालाब के सौंदर्यकरण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल शनिवार को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी 50 करोड रुपए की लागत से बने पूल का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसको लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सभी सरपंचों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं से गांव दर गांव जाकर मिले और सभी को रैली के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र संधू मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष गौतम राणा, रविंद्र बतोड़, मंडल उपाध्यक्ष राहुल राणा भी मौजूद रहे।

एनएचपीसी पार्बती जलविद्युत परियोजना, चरण-।। की सभी चार यूनिटो में बिजली का उत्पादन शुरू

संवाददाता
चंडीगढ़

एनएचपीसी ने पार्बती परियोजना चरण-।। की अंतिम और चौथी यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन सफलता पूर्वक दिनांक 16-04-2025 को 00:00 बजे पूरा कर लिया है। इससे पूर्व दिनांक 01-04-2025 को परियोजना की तीन यूनिटो का सफलता पूर्वक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही एनएचपीसी ने देश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है।

पार्बती-।। जलविद्युत परियोजना, जिसकी कुल संस्थापित क्षमता 800 मेगावाट (4 * 200 मेगावाट) है, यह एक 'रन ऑफ द रिवर' परियोजना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्बती नदी पर छोटे पॉण्डेज का निर्माण किया गया है। मणिकरण घाटी में पुलगा गांव के निकट 83.7 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध बनाकर पार्बती नदी की धारा को मोड़कर तथा पानी को 31.56 किलोमीटर लंबी हेड रेस सुरंग के माध्यम से सैंज घाटी तक ले जाया जा रहा है, जहां सिउंड गांव में पावर हाउस का निर्माण किया गया है। पुलगा और

सिउंड के बीच 863 मीटर की कुल ऊंचाई का उपयोग 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। हेड रेस सुरंग के साथ आने वाले, पांच नालों के पानी के मिलने से पार्बती के जल प्रवाह में और अधिक वृद्धि हुई है। पावर हाउस में 200 मेगावाट की 4 पेल्टन टर्बाइनें लगाई गई हैं। परियोजना की 31.56 किलोमीटर लंबी एचआरटी भारत की सबसे लंबी जलविद्युत सुरंग है। दो इन्कलाइन्ड प्रेशर शाफ्ट, जो प्रत्येक 1545.5 मीटर लंबी है, यह टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से खोदी गई दुनिया की सबसे लंबी इन्कलाइन्ड प्रेशर शाफ्ट सुरंगें हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य को इस परियोजना से 12% निःशुल्क ऊर्जा मिलेगी और 1% अतिरिक्त निःशुल्क ऊर्जा का उपयोग

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए किया जाएगा। परियोजना की आधारशिला तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 12 दिसंबर 1999 को रखी गई थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 11.09.2002 को 3919.59 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को मंजूरी दी। परियोजना का निर्माण सितंबर 2002 में शुरू हुआ था। निर्माण के दौरान परियोजना को कई चुनौतियों जैसे बादल फटना, अचानक बाढ़, बैक-स्लोप विफलता, भारी डिस्चार्ज के साथ सिल्ट और शियर जोन आदि का सामना करना पड़ा है। परियोजना की अनुमानित पूर्णता लागत 13,045 करोड़ रुपए है। परियोजना की डिजाइन ऊर्जा 3074 मिलियन यूनिट (एमयू) है। इस परियोजना के चालू होने से 520 मेगावाट क्षमता के पार्बती-।।क पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता भी 1262 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष बढ़ जाएगी।

परियोजना क्षेत्र में, एनएचपीसी ने 15 पुलों तथा लगभग 88 किलोमीटर सड़क-मार्ग का निर्माण किया है तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 112 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। एनएचपीसी ने सीएसआर के अंतर्गत कुल 27.83 करोड़ रुपए का व्यय किया है और इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां पूर्ण की हैं। परियोजना प्रभावित 20 लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, 349 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया है, जिनमें से 98% स्थानीय क्षेत्र से हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना के निर्माण के दौरान 1361 व्यक्तियों को परियोजना में रोजगार मिला है, जिनमें से 1171 हिमाचल के स्थानीय निवासी थे। 370 परियोजना प्रभावित परिवारों(पीएएफ) को आजीविका सहायता प्रदान की जा रही है। परियोजना प्रभावित परिवारों से 58 वाहन किराए पर लिए गए हैं। स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए सैंज में केन्द्रीय विद्यालय चलाया जा रहा है, जिसके संचालन पर प्रति वर्ष 04 करोड़ रूपए से अधिक व्यय हो रहा है। केन्द्रीय विद्यालय के कुल 422 छात्रों में से 411 छात्र स्थानीय क्षेत्र से हैं। कुल्लू में क्षेत्रीय अस्पताल भवन के विस्तार संबंधी निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत का सबसे बड़ा जलविद्युत विकास संगठन है, जिसके पास जलविद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर कमीशनिग तक सभी गतिविधियों को निष्पादित करने की क्षमता है। एनएचपीसी ने सौर एवं पवन ऊर्जा आदि के विकास क्षेत्र में भी विविध प्रसार किया है। इस परियोजना के निर्माण के पश्चात कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 8140.04 मेगावाट (संयुक्त उद्यम में 1681.7 मेगावाट सहित) है, जिसमें 23 जलविद्युत पावर स्टेशनों से 7771.20 मेगावाट, छह सौर ऊर्जा और एक पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 368.84 मेगावाट शामिल है।

शिक्षा मंत्री बैंस ने कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी पत्र वितरित किए

- पंजाब सरकार के सहयोग से रयात बाहरा ने जिला स्तरीय अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया

संवाददाता
मोहाली

रयात बाहरा विश्वविद्यालय ने पंजाब सरकार के सहयोग से भारत रत्न डॉ बीआर अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया। डॉ. अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निमार्ता थे और सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण के लिए एक महान व्यक्तित्व थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री एस. हरजोत सिंह बैंस मुख्य अतिथि थे। सभा को संबोधित करते हुए बैंस ने डॉ. अंबेडकर की अद्वितीय विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए उनके आजीवन समर्पण को उजागर किया।

कुलपति गुरविंदर सिंह बाहरा और रयात बाहरा समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहिल कपूर ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और उपस्थित लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में चांसलर बहरा ने एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और दलित बौद्ध आंदोलन के नेता के रूप में डॉ. अंबेडकर के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डाला तथा एक न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में, शिक्षा मंत्री ने कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी पत्र वितरित किए, जिनमें एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में आनंदपुर साहिब के सांसद मालविंदर सिंह कंग, जिला योजना बोर्ड, मोहाली की अध्यक्ष प्रभजोत कौर, पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष परमिंदर सिंह गोल्डी और मोहाली की डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल शामिल थे।